घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com **अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 258- रविवार 19- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये** RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हंगामा....

सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया,सीजेपी से जंतर-मंतर खाली करने का आग्रह...

अभिजीत दीपके पर फेंकी गई स्याही,भूख हड़ताल का किया ऐलान

नई दिल्ली,18 जुलाई 2026। दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर पिछले 20 दिन से अनशन पर बैठे पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सोशल मीडिया अभियान और प्रदर्शन पर भी कार्रवाई की है। सफदरजंग अस्पताल का कहना है कि आज सुबह सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी उनकी चिकित्सीय जांच चल रही है। जल्द ही इस बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उच्च न्यायालय के आदेश और सोनम वांगचुक की लगातार गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए आज उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदर्शन स्थल से उन्हें ले जाते समय सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गतिरोध उत्पन्न किया। पुलिस ने अनुरोध किया है कि सभी सीजेपी कार्यकर्ता

शांतिपूर्ण ढंग से जंतर-मंतर को खाली कर दें। सीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली पुलिसकर्मी सादे लिबास में प्रदर्शनस्थल पर पहुंचे थे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की।बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के दौरान आंदोलन के मुखिया बने अभिजीत दीपिके वहां पर उपस्थित नहीं थे। पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर कहना है कि इस दौरान वह स्नान करने गए थे। एक वीडियो संदेश में दीपिके ने कहा कि उन्हें अपने मित्र के यहां पुलिस ने जबरन हिरासत में रखा था। उनके साथ मारपीट की गई है। उन्होंने आंदोलन को जारी रखने की अपील की है।

जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान शनिवार को उस समय हंगामा मच गया, जब एक महिला ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके पर स्याही फेंक दी। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और घटना के कारणों की जांच में जुटी है।

सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने को खरगे और वेणुगोपाल ने बताया लोकतंत्र और संविधान पर धब्बा

पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस द्वारा सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराए जाने पर कांग्रेस ने तानाशाही करार दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने इसे लोकतंत्र और संविधान पर धब्बा बताया। खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चाहे मां गंगा को बचाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे प्रो. जीडी अग्रवाल हों, हरियाणा की महिला पहलवान हों, किसान हों, दलित-आदिवासी हों या पेपर लीक से प्रभावित छात्र सरकार ने किसी को नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि इस सरकार की नजर में कोई भी आवाज उठाने वाला 'देश द्रोही' या 'परजीवी' है। जंतर-मंतर पर जो हुआ वह लोकतंत्र और संविधान पर एक और काला धब्बा है। खरगे ने दावा किया कि 'छात्रों की गूंज' का कोटा और देहरादून में आगाज हुआ है और यह दिल्ली तक पहुंचेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना चाहिए था, लेकिन उसने सोनम वांगचुक को उनके धरने से हटा दिया। सरकार को करुणा और मानवता दिखानी चाहिए थी, लेकिन उसने फासीवादी तरीके से शांतिपूर्ण विरोध को तोड़ दिया।

सोनम वांगचुक की पत्नी ने सफदरजंग अस्पताल चिकित्सा अधीक्षक को लिखा पत्र,दूसरे अस्पताल ले जाने की मांग...

पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो ने शनिवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को पत्र लिखकर वांगचुक को अपनी पसंद के एक अन्य चिकित्सा केंद्र में स्थानांतरित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। पत्र में उन्होंने अस्पताल की कार्यप्रणाली और चिकित्सा संबंधी जानकारी को लेकर कई सवाल भी उठाए। गीतांजलि ने पत्र में आरोप लगाया कि अस्पताल की चिकित्सा टीम ने शनिवार सुबह उन्हें बताया कि सोनम वांगचुक का पोटेशियम स्तर घटकर 2.9 हो गया है, जबकि एक दिन पहले शाम 4:16 बजे यह 4.3 दर्ज किया गया था। उन्होंने इस अंतर पर सवाल उठाते हुए संबंधित चिकित्सकीय रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की। पत्र में यह भी कहा गया है कि वांगचुक की डिजिटल और प्रत्यक्ष निगरानी कर रहे चिकित्सकों से परिवार को मिलने की अनुमति नहीं दी गई। गीतांजलि ने आरोप लगाया कि अस्पताल में पारदर्शिता की कमी के कारण उनका भरोसा प्रभावित हुआ है। इसी वजह से परिवार ने वांगचुक को अपनी पसंद के मेडिकल सेंटर में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक से अनुरोध किया कि अस्पताल से छुट्टी देने से संबंधित सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाएं, ताकि वांगचुक को बेहतर चिकित्सा सुविधा और आवश्यक जांच के लिए दूसरे अस्पताल ले जाया जा सके। बाद में मीडिया से बातचीत में गीतांजलि जे. आंग्मो ने कहा कि सोनम वांगचुक की तबीयत फिलहाल ठीक है और वे यात्रा करने की स्थिति में होंगे।

सोनम वांगचुक में पानी की कमी और सीरम पोटैशियम का स्तर कम हुआ : मेडिकल बुलेटिन

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अध्यक्ष ने शनिवार को पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य रिपोर्ट के बारे में बताते हुए कहा कि 20 दिन से उपवास रहने के कारण उनमें पानी की कमी के लक्षण दिखे और उनका सीरम पोटैशियम का स्तर कम पाया गया। चिकित्सा अध्यक्ष ने बताया कि दिल्ली पुलिस आज सुबह उन्हें करीब 7:40 बजे वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया क्योंकि उन्होंने 20 दिन से कुछ खाया नहीं था इसलिए उनमें कमजोरी के लक्षण दिखाई दिए। भर्ती होने के समय, वे होश में थे और उनकी पल्स, ब्लड प्रेशर और 'ऑक्सीजन सैचुरेशन' स्थिर थे। उनमें पानी की कमी के लक्षण दिखे। उन्होंने बताया कि ब्लड गैस एनालिसिस से पता चला कि उन्हें 'कम्पन्सेटेड एसिडोसिस' है, 'सीरम पोटैशियम' का स्तर कम है और ब्लड शुगर 78 'एमजी/डीएल' है। दोबारा जांच में भी सीरम पोटैशियम का स्तर वैसा ही पाया गया। भर्ती होने के समय 'यूरिनरी कीटोन 1+' थे, जो दोपहर 1:00 बजे तक बढ़कर 3+ हो गए। स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया है कि सोनम को 'इंट्रावेनस (चतुर्थ) फ्लूइड' देने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह के इंट्रावेनस फ्लूइड, ओरल 'रिहाइड्रेशन फ्लूइड' या कोई अन्य दवा लेने से इनकार कर दिया है। उनकी सेहत के लिए सबसे बेहतर इलाज के मकसद से लगातार उनकी निगरानी और काउंसलिंग की जा रही है।

भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च

नई दिल्ली,18 जुलाई 2026। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 शनिवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हो गया। इस लॉन्चिंग को 'मिशन आगमन' नाम दिया गया है।

पहले इस मिशन को सुबह 11:30 बजे लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते इसे दोपहर 12.06 बजे प्रक्षेपित किया गया। हैदराबाद की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा बनाया गया विक्रम-1 तीन सॉलिड-फ्यूल स्टेज और एक लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल से चलता है। विक्रम-1 के प्रक्षेपण के साथ ही भारत ने ग्लोबल प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च मार्केट में कदम रख दिया है। यह भारत की कमर्शियल स्पेस क्षमताओं को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के पहले निजी

प्रधानमंत्री ने विक्रम-1 के सफल प्रक्षेपण के बाद स्काईरूट एयरोस्पेस के संस्थापकों से की बात,दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट 'विक्रम-1' के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी। उन्होंने कंपनी के सह-संस्थापक पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका से फोन पर बात कर कहा कि स्काईरूट ने आकाश में अपनी जड़ें गाड़ दी हैं और जमीन पर भी उन जड़ों को मजबूत किया है, जो देश के युवाओं को प्रेरणा देंगी। समयऔर कैलेंडर प्रधानमंत्री ने हैदराबाद स्थित निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित देश का पहला ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट 'विक्रम-1' के शनिवार को सफल प्रक्षेपण के बाद कंपनी के सह-संस्थापक पवन कुमार चंदना से इसरो के दफ्तर में फोन से बात करते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सफलता ने दिखा दिया है कि भारत निजी क्षेत्र की भागीदारी से भी अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में सक्षम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्काईरूट की युवा टीम ने प्रतिबद्धता और मेहनत से भारत मां की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।

तौर पर विकसित ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट विक्रम-1 की लॉन्चिंग का आईसीएमआर से सीधा प्रसारण देखा। उन्होंने इसके सफलतापूर्वक प्रक्षेपण को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।

इस मौके पर उन्होंने सभी वैज्ञानिकों को मिठाई खिलाई। उन्होंने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को बधाई दी। डॉ सिंह ने कहा कि स्काईरूट एयरोस्पेस को विक्रम-1 के सफल प्रक्षेपण पर हार्दिक बधाई। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का यह मिशन देश के तेजी से उभरते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह भारत की बढ़ती अंतरिक्ष तकनीकी क्षमता और विकसित हो रही स्पेस इकोनॉमी का प्रमाण है। यह उपलब्धि भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा का निधन

नई दिल्ली,18 जुलाई 2026। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा का शनिवार 18 जुलाई 2026 को बेंगलुरु के एक प्राइवेट अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने शाम 4 बजे अचानक से दिल का दौरा पड़ा। इससे पहले बुधवार यानी 16 जुलाई को उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई थी। इसके अलावा सीने में जकड़न,उम्र से जुड़ी अन्य समस्याएं भी सामने आई थी। उन्हें बेंगलुरु के मणिपाल अस्पताल में एडमिट कराया गया था। अब अस्पताल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हमें यह बताते हुए दुख हो रहा है कि श्रीमती चेन्नम्मा की हालत में पहले सुधार हो रहा था। आज शाम 4 बजे उन्हें जबरदस्त कार्डियक अरेस्ट हुआ। उन्हें बेंगलुरु के पुराने एयरपोर्ट रोड स्थित मनिपाल अस्पताल पर बुधवार देर रात एडमिट किया गया था। यहां आईसीयू में रखा गया था। शनिवार को जांच के दौरान उनमें किसी तरह की हलचल नहीं देखी गई, जिसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस दौरान गौड़ा, उनके बेटे और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी और परिवार के अन्य सदस्य फिलहाल अस्पताल में मौजूद थे।

अहमदाबाद में पटाखा फैक्टरी में आग से 9 की मौत,कई घायल

अहमदाबाद,18 जुलाई 2026। गुजरात के अहमदाबाद के वस्त्राल क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक पटाखा फैक्टरी में भीषण आग लग गयी। इस हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियां, एंबुलेंस, असलाली मिनी फाइटर, गजराज और अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त जयपाल सिंह राठौड़ ने आठ लोगों की मौत की पुष्टि की है। वस्त्राल क्षेत्र के रामोल-गटराड रोड स्थित महमूदपुरा इलाके में दोपहार को टैलेंट पटाखा फैक्टरी में अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी भीषण थी कि उसने कुछ ही देर में पूरी फैक्टरी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी और चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर की टीम और राहत व बचाव दल ने आठ लोगों के शवों के साथ घायलों त्वरित गति से फैक्टरी से बाहर निकाला। गंभीर घायलों में से 5 लोगों को एलजी

अस्पताल और 4 लोगों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य घायलों का भी उपचार चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही अहमदाबाद के मेयर और नगर आयुक्त भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

जांच में सामने आया है कि फैक्टरी का संचालन मेहुल डोडिया नामक व्यक्ति कर रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सेक्टर-2 के संयुक्त पुलिस आयुक्त जयपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि रामोल-गटराड रोड पर आरएएफ कैंप के पीछे खुले मैदान में शेड बनाकर मेहुल डोडिया पटाखा फैक्टरी चला रहा था। इस फैक्टरी का लाइसेंस पहले ही रद्द किया जा चुका था। इसके बावजूद यहां अवैध रूप से पटाखों का निर्माण जारी था। उन्होंने बताया कि अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। घटना की सूचना मिलते ही सबसे पहले आरएएफ की टीम, स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। रामोल पुलिस इस मामले में विस्फोटक अधिनियम तथा अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।

मेडिकल कॉलेज खोलने के नियमों में बड़ा बदलाव,अब किसी भी कंपनी को मिलेगी अनुमति

नई दिल्ली,18 जुलाई 2026। देश में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल कॉलेज खोलने से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। नए प्रावधानों के तहत अब कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कोई भी कंपनी मेडिकल कॉलेज स्थापित कर सकेगी। इससे पहले यह अनुमति केवल सेक्शन-8 (गैर-लाभकारी) कंपनियों तक सीमित थी।

क्या बदला है नियम?

अब तक केवल गैर-लाभकारी संस्थाओं को ही मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की अनुमति थी। सेक्शन-8 कंपनियां अपने लाभ को संस्थान के विकास या सामाजिक कार्यों में ही खर्च कर सकती थीं। लेकिन नए नियम लागू होने के बाद लाभ कमाने वाली कंपनियां भी निर्धारित मानकों का पालन करते हुए मेडिकल कॉलेज शुरू कर सकेंगी।

सरकार ने बताई बदलाव की वजह

सरकार का मानना है कि गैर-लाभकारी शर्त के कारण कई बड़े कॉर्पोरेट समूह मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने से बच रहे थे। साथ ही, अनौपचारिक रूप से मुनाफा कमाने की शिकायतें भी सामने आती थीं। सरकार का तर्क है कि कानूनी व्यवस्था बनने से निवेश बढ़ेगा, पारदर्शिता आएगी और कर (टैक्स) राजस्व में भी वृद्धि होगी। वर्ष 2017 में तत्कालीन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी पंजीकृत कंपनियों को मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दी थी। हालांकि, 2019 में एमसीआई की जगह एनएमसी बनने के बाद नियम सख्त कर दिए गए और केवल सेक्शन-8 कंपनियों को ही अनुमति दी गई।

मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला...4 लाख पेंशनर्स का इंतजार खत्म,छत्तीसगढ़ की बंदिश खत्म

नई दिल्ली,18 जुलाई 2026। मध्य प्रदेश के 4 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अब केंद्र सरकार जैसे ही अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाएगी, मध्य प्रदेश सरकार भी उसे तुरंत अपने यहां लागू कर देगी। सरकार इसके लिए अब पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की सहमति का इंतजार बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। यही वजह है कि दोनों राज्यों के वित्त विभागों ने इस संबंध में एक अहम संयुक्त आदेश जारी कर दिया है। यह नई व्यवस्था पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ से मंजूरी का 26 साल पुराना नियम समाप्त : पहले वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। उस समय राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत पेंशनर्स को लाभ देने के लिए दोनों राज्यों की आपसी सहमति अनिवार्य की गई थी। लेकिन इस कागजी औपचारिकता के कारण फाइलें अक्सर महीनों तक सरकारी दफ्तरों में अटकी रहती थीं। नतीजतन बुजुर्ग पेंशनर्स को अपने हक

के लिए 6-6 महीने तक लंबा इंतजार करना पड़ता था। अब इस पुराने पेंच को मध्य प्रदेश के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी और छत्तीसगढ़ के वित्त सचिव ने आपसी बैठक कर पूरी तरह हटा दिया है। इसलिए अब दोनों राज्य स्वतंत्र रूप से अपना कार्यकारी आदेश जारी कर सकेंगे।

केंद्र की तय सीमा से ज्यादा राहत देने पर रहेगी रोक : हालांकि इस नए नियम में एक जरूरी वित्तीय शर्त भी जोड़ी गई है। इसके अनुसार कोई भी राज्य केंद्र सरकार द्वारा घोषित दर से अधिक पेंशनर्स महंगाई राहत का भुगतान नहीं कर सकेगा। इसके अलावा दोनों राज्य भविष्य में आपस में केवल वित्तीय भार की जरूरी जानकारी साझा करेंगे। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह बेहद संवेदनशील निर्णय लिया है। इसके बाद अब बुजुर्गों को समय पर बढ़ा हुआ पैसा मिल सकेगा। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद प्रशासनिक लेटलतीफी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में जैसे ही नई दरें घोषित होंगी, बुजुर्गों के बैंक खातों में बढ़ी हुई राशि सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। इससे प्रदेश के लाखों परिवारों को बड़ी आर्थिक मजबूती मिलेगी।

वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना सरकार : यह पूरा मामला दोनों राज्यों के बंटवारे से जुड़ा हुआ है। असल में वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। उस समय राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था। इसके तहत दोनों राज्यों के बीच देनदारियों का बंटवारा हुआ।

भारत में जल्द आ सकते हैं प्लास्टिक के नोट...आरबीआई ने शुरू की तैयारी,10 और 20 रुपये के नोटों से होगी शुरुआत

नई दिल्ली,18 जुलाई 2026। भारत में जल्द ही 10 और 20 रुपये के प्लास्टिक (पॉलीमर) नोट देखने को मिल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। शुरुआत में यह एक पायलट प्रोजेक्ट होगा। अगर यह सफल रहा, तो आगे दूसरे मूल्य के नोट भी प्लास्टिक में जारी किए जा सकते हैं। आरबीआई की नोट छापने वाली कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने ऐसी कंपनियों से आवेदन मांगे हैं, जिन्हें सुरक्षा वाले पॉलीमर नोट बनाने का अनुभव हो। उद्देश्य सिर्फ विदेश से सामग्री मंगाना नहीं, बल्कि भारत में ही प्लास्टिक नोट बनाने की तकनीक विकसित करना है। इस टेंडर के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 18 अगस्त रखी गई है। पॉलीमर नोट कागज के नोटों से ज्यादा मजबूत होते हैं। ये जल्दी नहीं फटते, पानी और नमी से खराब नहीं होते और इन पर धूल भी कम लगती है। इसी वजह से इनकी उम्र ज्यादा होती है। दुनिया के 60 से अधिक देश पहले से प्लास्टिक के नोट इस्तेमाल कर रहे हैं।

ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के पार्टी दफ्तर पर बुलडोजर कार्रवाई,भारी फोर्स दिखी...

कोलकाता,18 जुलाई 2026। सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के 'अवैध रूप से निर्मित' कार्यालय को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इस पांच मंजिला दफ्तर को गिराने के लिए तीन बुलडोजर काम कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी का यह दफ्तर दक्षिण 24 परगना के अमताला-बारुईपुर रोड पर स्थित है। प्रशासन ने इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए पहले भी नोटिस जारी किया था। लेकिन इस पर अभिषक बनर्जी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद शनिवार को प्रशासन ने इस इमारत को ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सांसद अभिषेक बनर्जी का ये ऑफिस साउथ 24 परगना में स्थित है। तृणमूल कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी के एमपी ऑफिस को 'अवैध निर्माण' के आरोप में तोड़े जाने की कार्रवाई शुरू होने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। इस मकान के सामने जैसे ही सुबह सुबह

बुलडोजर पहुंचा, स्थानीय लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता और टीएमसी कार्यकर्ता भी यहां जमा हो गए। स्थिति तनावपूर्ण होता देख प्रशासन को ज्यादा सुरक्षाकर्मी बुलाने पड़े। सुरक्षा के लिहाज से यहां बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इससे पहले प्रशासन ने एक नोटिस चिपकाकर आरोप लगाया था कि यह इमारत बिना मंजूरी के बनाई गई थी। विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से यह कार्यालय बंद था। जिला प्रशासन का दावा है कि यह कार्यालय अवैध रूप से बनाया गया था। यह कार्यालय बिना किसी दस्तावेज़ के बनाया गया था। कार्यालय के निर्माण से संबंधित कोई वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया जा सका। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद ये दफ्तर बंद पड़ा हुआ था। डायमंड हार्बर में जब भी कोई बैठक होती थी, वह इसी कार्यालय में होती थी। इसका आयोजन तृणमूल कांग्रेस द्वारा किया जाता था। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार पिछली सरकार में बने अवैध इमारत और सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला रही है।

संपादकीय

नागरिकता का प्रश्न

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के समय वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटे जाने और उन्हें कथित तौर पर सरकारी योजनाओं से वंचित करने के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा, उससे भ्रम पूरी तौर पर दूर होना कठिन ही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से नाम कटने का मतलब नागरिकता खत्म होना नहीं है,क्योंकि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऐसा ही कहा था,लेकिन तब उसने यह भी जोड़ा था कि आयोग मतदाता सूची बनाते या उसे संशोधित करते समय नागरिकता की सीमित जांच कर सकता है। उसने ऐसी टिप्पणी इसलिए की थी,क्योंकि चुनाव आयोग को यह देखना होता है कि मतदाता भारतीय नागरिक है या नहीं? उसे यह देखने का अधिकार इसीलिए दिया गया, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का हक भारतीय नागरिकों को ही मिल सकता है। निःसंदेह चुनाव आयोग के पास यह अधिकार नहीं कि वह किसी की नागरिकता का निर्धारण करे,क्योंकि नागरिकता का निर्धारण तो भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत होता है और इसके अनुसार जन्म, वंश, भारत में लंबे समय से रहने आदि के आधार पर नागरिकता तय होती है।

समस्या यह है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। इसीलिए पिछले दिनों जब यह बात सामने आई कि पासपोर्ट यात्रा का दस्तावेज मात्र है,नागरिकता का प्रमाण नहीं, तब भी यह बहस उठी थी कि आखिर किसी की नागरिकता का निर्धारण किस प्रमाण पत्र से होगा? इस प्रश्न का कोई सीधा-सरल उत्तर तब तक नहीं मिल सकता,जब तक लोगों को नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता।

ध्यान रहे कि आधार,ड्राइविंग लाइसेंस के साथ पैन, राशन कार्ड आदि भी नागरिकता के दस्तावेज नहीं हैं। मतदाता पहचान पत्र भी नागरिकता का प्रमाणन नहीं करता। चुनाव आयोग की एसआइआर प्रक्रिया इसीलिए जटिल है,क्योंकि लोगों के पास ऐसे दस्तावेज बहुत कम हैं,जिनसे उनकी नागरिकता का आसानी से प्रमाणन हो जाए। अपने देश की एक अन्य समस्या यह है कि यदि कोई राशन कार्ड,आधार आदि बनवा ले तो फिर वह हर तरह के दस्तावेज हासिल कर सकता है- मतदाता पहचान पत्र से लेकर पासपोर्ट तक।

यह किसी से छिपा नहीं कि तमाम बांग्लादेशी घुसपैठियों ने ऐसा कर रखा है। यदि यह समझा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के यह कहने से समस्या का समाधान हो जाएगा कि चुनाव आयोग किसी की नागरिकता तय नहीं कर सकता तो यह सही नहीं। ऐसी किसी टिप्पणी से एसआइआर की प्रक्रिया भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि चुनाव आयोग को तो यह सुनिश्चित करना ही होगा कि मतदाता भारतीय नागरिक हो।

सड़क दुर्घटनाएँ : व्यक्तिगत लापरवाही नहीं... बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुशासन की चुनौती

डॉ. सत्यवान सौरभ
भिवानी,हरियाणा

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

भारत आज विश्व में सड़क दुर्घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित देशों में शामिल है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में लगभग 1.77 लाख लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई। यह संख्या किसी प्राकृतिक आपदा या महा मारी से कम नहीं है। प्रत्येक दिन सैकड़ों परिवार अपने किसी प्रियजन को खो देते हैं,हजारों लोग स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाते हैं और देश को उत्पादक मानव संसाधन तथा अरबों रुपये की आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। इसलिए सड़क दुर्घटनाओं को केवल चालक की लापरवाही,तेज गति या यातायात नियमों के उल्लंघन तक सीमित करके देखना वास्तविक समस्या से आँखें मूँदने जैसा है। यह वस्तुतः सार्वजनिक स्वास्थ्य,सड़कअव संरचना, कानून प्रवर्तन,आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं तथा प्रशासनिक समन्वय की व्यापक विफलता का परिणाम है।

सड़क सुरक्षा का प्रश्न सीधे नागरिकों के जीवन के अधिकार से जुड़ा है, जिसकी गारंटी भारतीय संविधान का अनुच्छेद-21 देता है। यदि कोई नागरिक सुरक्षित रूप से सड़क पर चल भी नहीं सकता, तो यह केवल उसकी व्यक्तिगत असाव धानी नहीं,बल्कि राज्य की जिम्मेदारी और शासन व्यवस्था की प्रभावशीलता पर भी प्रश्नचिह्न है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनेक मामलों में सरकारों को सुरक्षित सड़क अव संरचना,वैज्ञानिक सड़क निर्माण तथा प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

भारत में अधिकांश दुर्घटनाओं के पीछे सड़कों की खराब इंजीनियरिंग एक प्रमुख कारण है। अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट,अपर्याप्त संकेतक,टूटी हुई सड़कें,अवैज्ञानिक मोड़,प्रकाश व्यवस्था का अभाव तथा पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित मार्ग न होना दुर्घटनाओं को आमंत्रित करता है। शहरों में फुटपाथों पर अतिक्रमण,अवैध पार्किंग तथा अनियोजित यातायात व्यवस्था भी दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ाती है। सड़क निर्माण के दौरान गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की अनदेखी अंततः आम नागरिकों के जीवन पर भारी पड़ती है।

दूसरा महत्वपूर्ण कारण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव है। मोटर वाहन अधिनियम में कठोर दंड का प्रावधान होने के बावजूद तेज गति, शराब पीकर वाहन चलाना,हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग न करना तथा ओवरलोडिंग जैसी समस्याएँ लगातार बनी हुई हैं। कई स्थानों पर यातायात नियमों का पालन केवल पुलिस की उपस्थिति तक सीमित रहता है। यदि निगरानी व्यवस्था तकनीक आधारित और पारदर्शी हो,तो नियमों का पालन स्वतः बढ़ सकता है।

सड़क दुर्घटनाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट इसलिए भी माना जाता है क्योंकि दुर्घटना के बाद समय पर उपचार उपलब्ध न होना बड़ी संख्या में मौतों का कारण बनता है। स्वर्णिम घंटा के दौरान यदि पीड़ित को उचित चिकित्सा सहायता मिल जाए तो अनेक जीवन बचाए जा सकते हैं, किंतु ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में एंबुलेंस सेवाओं की कमी,ट्रॉमा सेंटरों का अभाव तथा अस्पतालों तक पहुँचने में देरी के कारण स्थिति गंभीर हो जाती है। कई बार पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय की कमी भी राहत कार्यों को प्रभावित करती है।

प्रशासनिक स्तर पर भी सड़क सुरक्षा अनेक विभागों में विभाजित उत्तरदायित्व का विषय है। सड़क निर्माण एक विभाग करता है,यातायात नियंत्रण पुलिस के पास होता है,स्वास्थ्य सेवाएँ किसी अन्य विभाग के अधीन होती हैं और स्थानीय निकायों की अपनी अलग भूमिका होती है। इस विखंडित व्यवस्था के कारण दुर्घटना रोकथाम के लिए समन्वित रणनीति विकसित नहीं हो पाती। परिणामस्वरूप जवाबदेही भी स्पष्ट नहीं रहती।

सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले सड़कों की इंजीनियरिंग को वैज्ञानिक और सुरक्षित बनाना आवश्यक है। प्रत्येक सड़क परियोजना में सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य किया जाए तथा दुर्घटना संभावित स्थानों की शीघ्र पहचान कर उनका सुधार किया जाए। पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों तथा दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को भी सड़क डिजाइन का अभिन्न भाग बनाया जाना चाहिए।

यातायात नियमों के पालन हेतु तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था को व्यापक बनाया जाना चाहिए। स्वचालित स्पीड कैमरे,सीसीटीवी नेटवर्क,कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित यातायात प्रबंधन तथा ई-चालान प्रणाली भ्रष्टाचार को कम करने के साथ-साथ नियमों के पालन को भी बढ़ावा देंगे। बार-बार नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस निलंबित करने तथा कठोर दंड लागू करने की आवश्यकता है।

आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करना भी अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर निश्चित दूरी पर आधुनिक ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाएँ,एंबुलेंस सेवाओं का विस्तार किया जाए तथा सभी अस्पतालों को दुर्घटना पीड़ितों का तत्काल उपचार सुनिश्चित करने के लिए बाध्य किया जाए। गुड समैरिटन दिशा-निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन भी आवश्यक है,ताकि घायल व्यक्ति की सहायता करने वाले नागरिक किसी कानूनी परेशानी के भय से पीछे न हटें।

सड़क सुरक्षा केवल कानून का विषय नहीं बल्कि सामाजिक व्यवहार का भी प्रश्न है। विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक सड़क सुरक्षा शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से नागरिकों में जिम्मेदार वाहन संचालन की संस्कृति विकसित की जानी चाहिए। अभिभावकों, शिक्षकों, मीडिया तथा नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

मेरा हक,मेरा सपना,मेरा लोकतंत्र : अब और इंतजार नहीं...

*** संसद में 33 % जगह का हक,लेकिन इंतजार की कोई सीमा नहीं**

*** आरक्षण का सूरज उदय हुआ,लेकिन महिलाओं के लिए अभी भी अंधेरा**

कृति आर.के.जैन
बड़वानी,मध्यप्रदेश

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना यह नहीं कि महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देर से मिला,बल्कि यह है कि कानून बनने के बाद भी उसका लाभ आज तक नहीं मिला। संविधान (106 वाँ संशोधन) अधिनियम,2023 पारित और अप्रैल 2026 में अधिसूचित हो चुका है, फिर भी उसका क्रियान्वयन जनगणना और परिसीमन तक टला है। 20 जुलाई 2026 से जंतर-मंतर पर प्रस्तावित अनिश्चित कालीन धरना केवल आंदोलन नहीं,बल्कि उस व्यवस्था से सीधा सवाल है जिसने अधिकार तो दिया,पर उसे लागू नहीं किया। आंदोलन कारी महिलाओं का स्पष्ट संदेश है : हमें भविष्य की संसद का आश्वासन नहीं, वर्तमान की संसद में अपना संवैधानिक स्थान चाहिए। यह केवल महिलाओं की पुकार नहीं,बल्कि लोकतंत्र के अधूरे वादे की गूंज है।

संविधान(106 वां संशोधन) अधि नियम,2023 ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का मार्ग खोला और इसे भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक मोड़ माना गया। अप्रैल 2026 में अधिसूचना जारी होने के बावजूद इसका क्रियान्वयन अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ दिया गया। यानी अधिकार संविधान में दर्ज है, लेकिन उसका लाभ अब भी टला हुआ है। यही कारण है कि महिला संगठनों का आक्रोश बढ़ रहा है। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी सहित अनेक महिला नेताओं का सवाल है–क्या आधी आबादी को आज भी लोकतंत्र में दूसरी श्रेणी का नागरिक मानकर इंतजार कराया जाएगा? यदि समान अधिकार संवैधानिक संकल्प है, तो उसका क्रियान्वयन भी बिना विलंब होना चाहिए। इस देरी के पीछे केवल संवैधानिक प्रक्रिया नहीं,बल्कि राज नीतिक गणित भी है। 2021 की जनगणना अब तक नहीं हुई,जबकि उसके बाद का परिसीमन देश का राजनीतिक संतुलन बदल सकता है। अनुमान है कि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर लगभग 850 हो सकती हैं। इससे उत्तर भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, जबकि जनसंख्या नियंत्रण में सफल दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी घटने की आशंका है। इसी कारण अप्रैल 2026 में लाए गए 131वें संविधान संशोधन और परिसीमन विधेयक पर विवाद गहरा गया। विपक्ष इसे राजनीतिक रणनीति मानता है,जबकि महिला संगठनों का आरोप है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर उसका क्रिया न्वयन टाल दिया गया। प्रक्रियाएं आवश्यक हैं,लेकिन जब वे अधिकारों में बाधा बनें,तो उन पर पुनर्विचार भी

आवश्यक हो जाता है।

इस देरी की सबसे बड़ी कीमत देश की महिलाएं चुका रही हैं। आज लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व 14 प्रतिशत से कम और राज्य विधानसभाओं में औसतन 10 प्रतिशत है। आरक्षण लागू होते ही सैकड़ों महिलाएं राष्ट्रीय नीति-निर्माण में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। पंचायतों और नगरीय निकायों में 50 प्रतिशत तक आरक्षण सिद्ध कर चुका है कि महिलाओं की भागीदारी से शासन अधिक संवेदनशील,जवाबदेह और जनहितकारी बनता है। जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को नई प्राथमिकता मिली है। जब गांव से नगर तक महिलाएं नेतृत्व क्षमता साबित कर चुकी हैं,तब संसद के द्वार उनके लिए प्रतीक्षा का प्रतीक बने रहना लोकतंत्र की बड़ी विडंबना है।

इस पृष्ठभूमि में महिला आरक्षण के लिए राष्ट्रीय गठबंधन सहित अनेक महिला संगठनों की मांग केवल राजनीतिक आग्रह नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक न्याय की अपेक्षा है। उनका कहना है कि सरकार यदि महिला सशक्तीकरण के प्रति प्रतिबद्ध है, तो वर्तमान लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण लागू कर जनगणना व परिसीमन की शर्त हटाए। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग,दलित,आदिवासी व अन्य वंचित वर्गों की महिलाओं के लिए उप-आरक्षण सुनिश्चित हो। वे चुनावी व्यय में सरकारी सहायता और महिलाओं के नाम पर पुरुष रिश्तेदारों द्वारा संचालित प्रतिनिधि राजनीति पर रोक की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर महिला संगठन मानसून सत्र में संवैधानिक संशो धन,जंतर-मंतर पर धरना और देशभर में जनजागरण अभियान की घोषणा कर चुके हैं।

वास्तव में यह संघर्ष कुछ सीटों का नहीं, लोकतंत्र की आत्मा का है। लोकतंत्र की मजबूती केवल मतदान नहीं,निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी से तय होती है। शिक्षा,विज्ञान,न्यायपालिका,सेना, उद्योग,कृषि,प्रशासन और अंतरिक्ष में क्षमता सिद्ध कर चुकी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रशासनिक प्रक्रियाओं के नाम पर टालना लोकतांत्रिक न्याय के विपरीत है। अनेक लोकतंत्रों ने सिद्ध किया है कि नीति-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी से शासन अधिक संवेदनशील,पारदर्शी और जवाबदेह बनता है। इसलिए महिला आरक्षण केवल महिला मुद्दा नहीं,बल्कि सामाजिक न्याय,समावेशी शासन,आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रश्न है। आधी आबादी की आवाज निर्णय प्रक्रिया में बराबरी से न सुनी जाए,तो विकास अधूरा रहेगा।

सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कानून बनाना नहीं, उस पर विश्वास बनाए रखना है। यदि संवैधानिक अधिकार वर्षों तक लागू न हों,तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि वे अधिकार हैं या केवल राजनीतिक घोषणा। जनगणना और परिसीमन आवश्यक संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं,लेकिन उन्हें महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की शर्त बना देना संविधान की समान अवसर की भावना के अनुरूप नहीं है। राजनीतिक इच्छा शक्ति हो,तो ऐसा समाधान संभव है जिससे जनगणना और परिसीमन समय पर हों और महिलाओं का संवैधानिक अधिकार प्रतीक्षा का शिकार न बने। लोकतंत्र की विश्वसनीयता अधिकार टालने में नहीं,उन्हें समय पर लागू करने के साहस में निहित है।

अब समय केवल निर्णय का नहीं, लोकतांत्रिक संकल्प निभाने का है। 20 जुलाई से जंतर-मंतर पर शुरू होने वाला आंदोलन किसी सरकार के विरोध का नहीं, बल्कि समान अधिकारों की लोकतांत्रिक पुकार है। यदि भारत विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना चाहता है, तो आर्थिक प्रगति के साथ राजनीतिक समानता भी सुनिश्चित करनी होगी। महिलाओं को प्रतीक्षा नहीं,नेतृत्व का अधिकार चाहिए। लोकतंत्र की सार्थकता कानून बनाने में नहीं,उसे समय पर लागू करने में है। आधी आबादी अब मौन दर्शक नहीं,समान अधिकार, सम्मान और प्रतिनिधित्व की दावेदार है। इतिहास गवाह है–अधिकार जितनी देर से मिलते हैं,लोकतंत्र उतना कमजोर होता है।

दान की दुहाई और खुद इससे करे रुश्वाई

चन्द्रकांत खुंटे क्रांति गरियाबंद,छत्तीसगढ़

मानव समाज में दान को हमेशा से सबसे बड़ा पुण्य और परोपकार का माध्यम माना गया है। प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक प्रवचनों तक,हर जगह दान की महिमा गाई जाती है। समाज को त्याग,करुणा और दूसरों की सहायता करने का उपदेश देने वाले चेहरों की कोई कमी नहीं है। परंतु,इस व्यवस्था का सबसे स्याह और कड़वा सच तब सामने आता है,जब दान की बड़ी-बड़ी दुहाई देने वाले लोग स्वयं कभी एक तिनका भी दान नहीं करते। इसके विपरीत,वे दूसरों के हिस्से का अधि कार,उनकी मेहनत और आजीविका को बड़ी बेरहमी से निगल जाते हैं। यहाँ यह बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि आखिर जो लोग दिन-रात धर्म, परोपकार और नीति की बातें करते हैं, वे स्वयं इस आचरण से कोसों दूर क्यों रहते हैं? क्या उन्हें दूसरों का हिस्सा खाते हुए पाप-पुण्य का या ईश्वर का कोई भय नहीं सताता?

इस विडंबना को समझने के लिए सबसे पहले उस पाखंड के मनोविज्ञान को समझना होगा,जो समाज के एक रसूखदार और शोषक वर्ग में गहराई से पैठा होता है। दान की दुहाई देना अक्सर एक सामाजिक और नैतिक कवच की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के हक को मारकर अपनी तिजोरियां भर रहा है, वह समाज में अपनी छवि को पवित्र और दयालु बनाए रखने के लिए धर्म और दान का सहारा लेता है। मंचों पर बैठकर परोपकार की बातें करना बहुत आसान और मुफ़्त होता है,जबकि वास्तव में अपनी जेब से कुछ देना या किसी भूखे का पेट भरना आत्मत्याग की मांग करता है। इस वर्ग के लिए दान की बातें करना केवल एक मुखौटा है,ताकि उनकी लूट पर किसी की नजर न पड़े और समाज उन्हें एक मार्गदर्शक के रूप में देखता रहे।

दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि दूसरों के हिस्से को मारकर खाने वाले इन लोगों के मन में पाप-पुण्य का भय क्यों नहीं होता? इसका सीधा उत्तर यह है कि इन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से पापऔर पुण्य की परिभाषाओं का ही बाजारीकरण कर दिया है। इनके भीतर यह अंधविश्वास या झूठा अहंकार होता है कि वे चाहे जितना भी आर्थिक या सामाजिक शोषण कर लें,अंत में किसी तीर्थयात्रा, किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान या किसी मंदिर में गुप्त दान देकर वे अपने सारे पापों से मुक्ति पा लेंगे। वे ईश्वर को एक व्यापारी की तरह देखते हैं, जिसके साथ वे अपनी अवैध कमाई का एक छोटा सा हिस्सा साझा करके अपने पापों का सौदा कर सकते हैं। जब धर्म की समझ इतनी संकुचित और विकृत हो जाए,तो अंतरात्मा का भय अपने आप समाप्त हो जाता है।

इसके अलावा,पूंजीवादी और सामंती मानसिकता का शिकार यह वर्ग यह मानता ही नहीं कि वे किसी दूसरे का हिस्सा खा रहे हैं। उनके भीतर एक तीव्र आत्म-मुग्धता होती है,जो उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि समाज का कमजोर वर्ग उनके अधीन रहने के लिए ही पैदा हुआ है। वे दूसरों की लाचारी, विस्थापन और भुखमरी को उनका भाग्य या अकर्मण्यता मान लेते हैं,न कि अपनी व्यवस्था जनित लूट का परिणाम। जब शोषक के मन में यह ग्लानि ही नहीं होगी कि वह किसी का अधिकार छीन रहा है, तो उसे पाप का बोध कैसे होगा?

इस सामाजिक विद्रूपता का एक और भयावह पहलू यह है कि यह शोषक वर्ग दान और धर्म को एक प्रकार के निवेश की तरह देखता है। वे बड़े-बड़े आयोजनों में लाखों रुपये खर्च करके अपनी झूठी प्रतिष्ठा की नींव मजबूत करते हैं, ताकि उस प्रतिष्ठा की आड़ में वे निर्धनों और मज़दूरों के अधिकारों का और अधिक दमन कर सकें। जो मज़दूर दिन-रात पसीना बहाकर उनके कारखानों,खेतों या इमारतों को खड़ा करता है,उसे उसकी सही मज़दूरी देने में इन दानियों के हाथ कांपने लगते हैं। दूसरों की भूख और बेबसी पर जो साम्राज्य खड़े होते हैं, वे कभी न्यायसंगत नहीं हो सकते। यह उस संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है जहाँ एक भूखे बच्चे के मुंह से निवाला छीनकर,धर्म के नाम पर भंडारे आयोजित करने का पाखंड रचा जाता है।

ऐसी स्थिति में पाप-पुण्य का भय केवल एक कमज़ोर मानसिक धारणा बनकर रह जाता है। जब कानून और न्याय की व्यवस्था भी रसूखदारों के पक्ष में झुकी हुई नज़र आती है,तो शोषक वर्ग का यह विश्वास और पक्का हो जाता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे यह भूल जाते हैं कि किसी मज़लूम की आह और उसके अधिकारों का हनन समाज के भीतर एक ऐसे असंतोष और आक्रोश को जन्म देता है,जो अंततः पूरी व्यवस्था को खोखला कर देता है।

अंततः,यह पूरी स्थिति समाज की उस सोई हुई चेतना को दर्शाती है, जहाँ लोग शब्दों के आडंबर से प्रभावित होकर व्यक्ति के कर्मों को देखना भूल जाते हैं। जब तक हम दान की खोखली दुहाई देने वालों के वास्तविक आचरण और उनकी कथनी-करनी के अंतर को नहीं पहचानेंगे,तब तक यह शोषण जारी रहेगा। सच्चा धर्म और पुण्य किसी के अधिकार को छीनकर झूठी सहानुभूति दिखाना नहीं, बल्कि दूसरों के हिस्से का सम्मान करना और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना है।

भारत के इतिहास में रचा बसा है आमरण अनशन

दुर्गेश्वर राय,गोरखपुर,उत्तर प्रदेश

देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ी परीक्षा नीट की विसंगतियों और प्रशासनिक पारदर्शिता के सवालों को लेकर सोनम वांगचुक का दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनशन जारी है। आज के इस आधुनिक और तकनीकी युग में भी अपनी देह को दांव पर लगा देना नागरिक प्रतिरोध का प्रखर माध्यम है। सोनम वांगचुक का यह वर्तमान संघर्ष दरअसल भारत के ऐतिहासिक सिलसिले का एक नवीनतम कड़ी है। आमरण अनशन से सामान्य आशय है भोजन का परित्याग करना। लेकिन भारत में आमरण अनशन का इतिहास,दमन और अन्याय के खिलाफ अपनी देह को ही प्रतिरोध का सबसे मारक हथियार बना देने की एक अनूठी गाथा है। जब संवाद के सारे तार्किक रास्ते बंद हो जाते हैं और सत्ता बहरी हो जाती है, तब आत्मा की आवाज को बुलंद करने के लिए इस आत्म-पीड़न के मार्ग को चुना जाता है। भारतीय संस्कृति में रचे-बसे प्राचीन प्रायोपवेशन यानी अन्न-जल त्याग कर मृत्यु का वरण करने की आध्यात्मिक परंपरा को आधुनिक राजनीति में एक लोकतांत्रिक अस्त्र के रूप में बदलने का काम हमारे महापुरुषों ने किया। ब्रिटिश हुकूमत के दमनकारी दौर से लेकर स्वतंत्र भारत की चुनी हुई सरकारों तक,इस नैतिक हथियार ने बार-बार सत्ता के अहंकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें कोई रक्तपात नहीं होता, कोई शस्त्र नहीं उठता,लेकिन फिर भी विरोधी का हृदय हिल उठता है।

इस विधा को एक राजनैतिक और नैतिक आंदोलन के रूप में वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जाता है। गांधी जी ने अपने जीवन में कुल 17 बार उपवास या अनशन का सहारा लिया। उनका मानना था कि अनशन विरोधी के भीतर सोई हुई इंसानियत और संवेदना को जगाने का एक आध्यात्मिक प्रयास है। साल 1932 में यरवदा जेल में ब्रिटिश सरकार के सांप्रदायिक पंचाट के खिलाफ किया गया उनका आमरण अनशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। गांधी जी के अनशनों की सबसे बड़ी रोचकता यह थी कि वे अपने प्राणों को दांव पर लगाकर विरोधी पक्ष के तर्कों को ही कुंद कर देते थे।

स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा मोड़ भी आया जब इस अहिंसक हथियार को क्रांतिकारियों ने जेल की काल कोठरियों में अपनी गरिमा की रक्षा के लिए अपनाया। लाहौर सेंट्रल जेल में बंद भारतीय कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के खिलाफ 13 जुलाई 1929 को भगत सिंह और उनके साथियों के साथ मिलकर महज 25 वर्ष के युवा जतिन दास ने भूख हड़ताल शुरू की। ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता का आलम यह था कि उन्होंने जतिन दास को जबरन खाना खिलाने (फोर्स-फीडिंग) की हर मुमकिन कोशिश की,यहाँ तक कि उनके पीने के पानी के घड़ों में दूध मिला दिया गया ताकि वे पानी पिएं तो उनका उपवास टूट जाए। लेकिन जतिन दास ने पानी पीना ही छोड़ दिया। लगातार 63 दिनों तक अन्न-जल का एक कतरा भी न लेने के कारण 13 सितंबर 1929 को उन्होंने हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस शहादत ने देश में क्रांति की ऐसी अग्नि भड़काई कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई। इसी तरह उत्तराखंड के वीर सेनानी श्रीदेव सुमन ने टिहरी रियासत के सामंती राजा के अत्याचारों के खिलाफ जेल में 84 दिनों का ऐतिहासिक अनशन किया और 25 जुलाई 1944 को शहीद हो गए,जो यह साबित करता है कि अनशन केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं,बल्कि आंतरिक तानाशाही के खिलाफ भी उतना ही असरदार था।

आजादी के बाद जब देश को लगा कि अब अनशनों का दौर बीत चुका है,तब स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने यह हथियार एक नए रूप में प्रकट हुआ। इसका सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ साल 1952 में आया,जब गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु ने तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग आंध्र राज्य की मांग को लेकर अपनी ही चुनी हुई सरकार के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। 56 दिनों के कठिन अनशन के बाद जब उनका निधन हुआ,तो पूरे दक्षिण भारत में जन-आक्रोश भड़क उठा जिसे संभालना सरकार के बस में नहीं रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को तुरंत झुकना पड़ा और भाषाई आधार पर देश के पहले राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा करनी पड़ी। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास की एक ऐसी रोचक और जटिल पहेली है, जिसने आगे चलकर पूरे देश के मानचित्र को बदलने यानी राज्यों के पुनर्गठन का आधार तैयार कर दिया।

समय बदला,तकनीक बदली और 21वीं सदी आते-आते आमरण अनशन का स्वरूप भी बेहद आधुनिक और व्यवस्था-परिवर्तनकारी हो गया। मणिपुर की आयरन लेडी इरोम चानू शर्मिला ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के खिलाफ साल 2000 में एक ऐसा अनशन शुरू किया जो दुनिया के इतिहास में सबसे लंबा,करीब 16 वर्षों तक चलने वाला प्रतिरोध बना। सरकार उन्हें जिंदा रखने के लिए नाक की नली से जबरन लिक्विड डाइट देती रही। वहीं दूसरी ओर, साल 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में किया गया अनशन आधुनिक युग का सबसे बड़ा जन-उबाल था। इस अनशन की रोचकता यह थी कि इसने सोशल मीडिया और तकनीक के दौर में पूरे देश के युवाओं को सड़कों पर ला खड़ा किया,जिसके दबाव में संसद को जन लोकपाल कानून की दिशा में कदम बढ़ाना पड़ा। हाल के वर्षों में लद्दाख की संवेदनशील संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए सोनम वांगचुक द्वारा कड़ाके की ठंड में किया गया 21 दिनों का जलवायु उपवास यह दिखाता है कि आज भी यह माध्यम उतना ही प्रासंगिक है।

इस ऐतिहासिक कड़ी में और भी ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी न्यायसंगत मांगों के लिए सत्ता की हठधर्मिता के आगे झुकने से इंकार कर दिया। पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ को लेकर चले लंबे सीमा विवाद के दौरान सिख नेता दर्शन सिंह फेरुमान ने साल 1969 में अमृतसर में आमरण अनशन का रुख किया था और लगातार 74 दिनों तक अटूट संकल्प बनाए रखने के बाद अस्पताल में उनका प्राणोत्सर्ग हो गया। वहीं पर्यावरण संरक्षण और जीवनदायिनी मां गंगा की अविरल धारा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर और विख्यात पर्यावरणविद् स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद (प्रोफेसर जी. डी. अग्रवाल) ने सरकारों की उदासीनता के खिलाफ कई बार उपवास किए। साल 2018 में गंगा नदी के लिए विशेष संरक्षण अधिनियम को पारित कराने की मांग को लेकर वे ऋषिकेश में अनशन पर बैठे और लगातार 111 दिनों के इस अभूतपूर्व तथा तपोमय संघर्ष के बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी,जिसने विकास और प्रकृति के अंतर्संबंधों पर एक गंभीर वैश्विक विमर्श को जन्म दिया। इन विभूतियों के आत्म-बलिदान के उदाहरण यह पुख्ता करते हैं कि चाहे क्षेत्रीय अस्मिता का प्रश्न हो या प्रकृति की रक्षा का, भारत की मिट्टी ने हमेशा ऐसे साधकों को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी देह को ही प्रतिरोध की सर्वोच्च समिधा बना दिया।

आमरण अनशन का यह पूरा सफरनामा भारतीय लोकतंत्र की एक अद्भुत ताकत को बयां करता है। यह स्पष्ट करता है कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता की सामूहिक चेतना और उसके नैतिक संकल्प में होती है,न कि सत्ता के गलियारों में।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

C M Y K

सड़क पर धान रोपकर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, 10 साल से बदहाल रास्ते के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन

पंडोपारा के ग्रामीणों ने कीचड़ बनी सड़क को बनाया खेत, बोले- चुनाव में वादे, बाद में भूल जाते हैं जनप्रतिनिधि

-संवाददाता-
अंबिकापुर/लखनपुर,18 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत पुहपुटरा के आश्रित ग्राम चिलबिल स्थित पंडोपारा के ग्रामीणों ने वर्षों से बदहाल सड़क के विरोध में शुक्रवार को अनोखा प्रदर्शन किया। ग्राम पुहपुटरा से पंडोपारा होते हुए सिंगीटाना जाने वाली जर्जर सड़क पर ग्रामीणों ने धान की रोपाई कर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। सड़क की हालत इतनी खराब है कि बरसात में वह खेत जैसी दिखाई देने लगती है। इसी स्थिति को प्रतीकात्मक रूप देते हुए ग्रामीणों ने सड़क को ही धान का खेत बना दिया। ग्रामीणों का कहना है कि करीब एक दशक से इस सड़क के निर्माण की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। उनका आरोप है कि यह क्षेत्र प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल के विधानसभा क्षेत्र में आता है, बावजूद इसके सड़क निर्माण की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई। चुनाव के समय सड़क बनाने के वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जनप्रतिनिधि इस समस्या को भूल जाते हैं।

बरसात में बन जाती है कीचड़ की दलदल

ग्रामीणों ने बताया कि बारिश शुरू होते ही सड़क पूरी तरह कीचड़ और जलभराव से भर जाती है। बड़े-बड़े गड्ढों के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। स्कूली बच्चे रोजाना फिसलकर गिरते हैं, जबकि दोपहिया वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे हालात में ग्रामीणों ने सड़क पर धान की रोपाई कर शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की।

पंडो परिवारों की बढ़ी मुश्किलें,एंबुलेंस भी नहीं पहुंच पाती

ग्रामीणों के अनुसार इस मार्ग से जुड़े क्षेत्र में विशेष पिछड़ी जनजाति पंडो समुदाय के करीब 10 परिवार निवास करते हैं। सड़क की बदहाली के कारण इन परिवारों का आवागमन बुरी तरह प्रभावित है। सबसे गंभीर स्थिति तब होती है, जब किसी मरीज या गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना पड़ता है। सड़क खराब होने के कारण एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती,जिससे ग्रामीणों को मरीजों को खाट पर उठाकर एक से दो किलोमीटर तक पैदल ले जाना पड़ता है।

मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति का आरोप

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क की समस्या से सरपंच, सचिव और संबंधित विभागीय अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन हर बार केवल अस्थायी मरम्मत कर औपचारिकता पूरी कर दी गई। स्थायी निर्माण नहीं होने के कारण हर बारिश में सड़क फिर से जर्जर हो जाती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल सड़क निर्माण कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। अब इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधि ग्रामीणों की वर्षों पुरानी समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाते हैं, इस पर सभी की नजर रहेगी।

मोबाइल देखने के लिए पेड़ के नीचे बैठे चार बच्चे आकाशीय बिजली गिरने से दो मासूमों की मौत

सरगुजा के नागम गांव में दर्दनाक हादसा, दो सगे भाई गंभीर रूप से झुलसे,बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे नहीं रुकने की अपील

-संवाददाता-
लुंड्रा/अम्बिकापुर,18 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र के नागम गांव में शुक्रवार शाम आकाशीय बिजली गिरने से दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठकर मोबाइल देख रहे चार बच्चे अचानक बिजली की चपेट में आ गए। हादसे में दो 12 वर्षीय मासूमों की मौके पर ही मौत हो गई,जबकि दो सगे भाई गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों का अस्पताल में उपचार जारी है और चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम करीब पांच बजे नागम गांव में हल्की बारिश शुरू हुई थी। बारिश से बचने के लिए गांव के चार बच्चे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वे मोबाइल देख रहे थे,तभी अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली सीधे पेड़ पर आ गिरी। बिजली का जोरदार झटका लगते ही चारों बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। आसपास मौजूद ग्रामीण धमाके की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे और तत्काल सभी बच्चों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक दो बच्चों की मौत हो चुकी थी।

दो मासूमों की गई जान,दो भाई अस्पताल में भर्ती : हादसे में रंजीत लोहरा (12 वर्ष),पिता नगेशिया लोहरा और रोशन नगेशिया (12 वर्ष),पिता विजय नगेशिया की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं प्रभु राम (11 वर्ष) और उसका बड़ा भाई दिनेश (13 वर्ष) गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है।

गांव में पसरा मातम : इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे नागम गांव में शोक का माहौल है। मृत बच्चों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश अधिक तेज नहीं थी,इसलिए बच्चों को किसी बड़े खतरे का अंदाजा नहीं था। लेकिन देखते ही देखते आकाशीय बिजली ने दो परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पंचनामा कार्रवाई के बाद दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिए गए।

बारिश के दौरान बरतें सावधानी : यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि बारिश और गरज-चमक के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होना या बैठना बेहद खतरनाक हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार बिजली अक्सर ऊंचे और अकेले खड़े पेड़ों पर गिरती है। ऐसे मौसम में खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहकर सुरक्षित भवन या पक्के आश्रय में शरण लेना चाहिए। इससे आकाशीय बिजली जैसी घटनाओं से बचा जा सकता है।

सरगुजा में पहली बार लगी स्पेशल लोक अदालत

34 चेक बाउंस मामलों का समझौते से निपटारा

5 साल से लंबित विवाद भी सुलझे,लाखों रुपए का भुगतान कर पक्षकारों ने खत्म किया मनमुटाव

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण,नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देश पर शनिवार को सरगुजा जिले में पहली बार धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम (चेक बाउंस) से जुड़े मामलों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण के लिए स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष शक्ति सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में हुआ। स्पेशल लोक अदालत का शुभारंभ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। अंबिकापुर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालय सीतापुर में गठित विशेष खंडपीठों के माध्यम से कुल 34 चेक बाउंस प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर सफल निराकरण किया गया। वर्षों से लंबित मामलों में समझौता होने से पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिली।

75 हजार का चेक बाउंस मामला समझौते से सुलझा

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी गिरिवर सिंह राजपूत की खंडपीठ में एक मामले में परिवादी ने अनावेदक को डेढ़ लाख रुपए का ऋण दिया था। भुगतान के लिए दिए गए 75 हजार रुपए के चेक के अनादर के बाद मामला न्यायालय पहुंचा। दोनों पक्षों के बीच पुराने संबंध होने के बावजूद पैसों के विवाद से रिश्तों में खटास आ गई थी। स्पेशल लोक अदालत में समझाइश के बाद अनावेदक ने 75 हजार रुपए का भुगतान कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने राजीनामा कर विवाद समाप्त कर दिया।

6 लाख रुपए का भुगतान कर खत्म हुआ विवाद : प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी पूजा मंडावी की खंडपीठ में एक मामले में परिवादी ने अनावेदक को 6 लाख रुपए दिए थे। चेक अनादरण के बाद मामला न्यायालय में लंबित था। लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति बनने पर अनावेदक ने मौके पर ही 6 लाख रुपए का भुगतान किया और प्रकरण का आपसी समझौते से निराकरण हो गया।

2018, 2020 और 2021 से लंबित मामले भी सुलझे

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी प्रांजलि नेताम की खंडपीठ में वर्ष 2018, 2020 और 2021 से लंबित तीन अलग-अलग चेक बाउंस मामलों में भी पक्षकारों ने आपसी सहमति से समझौता किया। चेक राशि लौटाने के बाद सभी मामलों का राजीनामे के माध्यम से निराकरण किया गया।

लंबित मामलों के निपटारे में मिली बड़ी सफलता

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव लीनम बनसोड़े ने बताया कि जिले में पहली बार आयोजित इस स्पेशल लोक अदालत में पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित चेक बाउंस मामलों का भी सफल निराकरण हुआ। इससे न केवल न्यायालयों का लंबित भार कम हुआ, बल्कि पक्षकारों के बीच आपसी संबंध भी पुनः स्थापित हुए। अधिकारियों ने इसे वैकल्पिक विवाद निपटान व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

अंबिकापुर के दिव्यांश ने SSC JE में दिखाई प्रतिभा, ऑल इंडिया रैंक-81 के साथ CPWD में बने जूनियर इंजीनियर

सिविल ब्रांच में देशभर में 81वीं रैंक,होलीक्रॉस से पढ़ाई और रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से किया बीई

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

शहर के होनहार युवा दिव्यांश तिवारी ने कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर परीक्षा-2025 में शानदार सफलता हासिल कर अंबिकापुर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। दिव्यांश ने परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक-81 प्राप्त की है। वहीं सिविल इंजीनियरिंग श्रेणी में उनकी ऑल इंडिया रैंक-61 रही। इस उपलब्धि के साथ उनका चयन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर हुआ है। दिव्यांश, अंबिकापुर के केदारपुर चर्च के सामने रहने वाले राकेश तिवारी एवं वसुधा तिवारी के पुत्र हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा होलीक्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अंबिकापुर से हुई। स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने प्री-इंजीनियरिंग परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर में सिविल इंजीनियरिंग शाखा में प्रवेश लिया। पढ़ाई के दौरान वे मेरिट छात्र रहे, जिसके कारण उनकी कॉलेज फीस भी माफ रही। बीई की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिव्यांश ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। नियमित अध्ययन, अनुशासित दिनचर्या और लगातार मेहनत के दम पर उन्होंने SSC JE-2025 में देशभर में 81वीं रैंक हासिल कर सफलता का नया मुकाम प्राप्त किया। दिव्यांश ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, शिक्षकों और कठिन परिश्रम को दिया है। उनका कहना है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और तैयारी निरंतर की जाए तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल की जा सकती है। दिव्यांश की इस उपलब्धि पर परिवार, शिक्षकों,मित्रों और शहरवासियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उनकी सफलता अंबिकापुर सहित सरगुजा के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है।

सरस्वती शिशु मंदिर में छात्र संसद के पदाधिकारियों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

शहर के सरस्वती शिशु मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को शिशु भारती एवं छात्र संसद के नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरस्वती शिक्षा संस्थान रायपुर के सचिव लक्ष्मण राव मगर थे। अध्यक्षता संस्था के उपाध्यक्ष अनिल सिंह मेजर ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में संगीता मगर, प्रतिमा त्रिपाठी एवं नगर निगम के सहायक महापौर मनीष सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन एवं दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। विद्यालय की प्राचार्या मीरा साहू ने अतिथियों का स्वागत एवं परिचय कराया। वहीं उमेश कुशवाहा ने छात्र संसद के गठन का उद्देश्य बताते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता,अनुशासन और दायित्वबोध का विकास होता है। समारोह में शिशु,बाल,कन्या एवं तरुण भारती के नवचयनित पदाधिकारियों को बैज पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने सभी पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। छात्र-छात्राओं ने अपने दायित्वों का ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करने का संकल्प लिया। अपने संबोधन में लक्ष्मण राव मगर ने कहा कि गुरु से प्राप्त शिक्षा और संस्कार ही विद्यार्थी के जीवन को सही दिशा देते हैं।

'छात्रों की गूंज' अभियान के तहत शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

युवा कांग्रेस-एनएसयूआई ने छात्रावासों और कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों से किया संवाद,पेपर लीक व रोजगार के मुद्दों पर मांगी पारदर्शी व्यवस्था

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई ने जिले में चल रहे 'छात्रों की गूंज' अभियान के तहत छात्रावासों, कोचिंग संस्थानों और विभिन्न अकादमियों में पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद किया। अभियान के दौरान छात्रों की समस्याएं सुनी गईं तथा शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और रोजगार जैसे मुद्दों पर उनकी राय ली गई। अभियान का संचालन आदित्येश्वर शरण सिंह देव के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। युवा कांग्रेस आरटीआई सेल के चेयरमैन हिमांशु जायसवाल और विश्वविद्यालय अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों से मुलाकात कर उनसे जाना कि वे किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं। इस दौरान छात्रों का पंजीयन भी किया गया, ताकि उनके सुझावों और समस्याओं को संकलित कर आगे संबंधित स्तर तक पहुंचाया जा सके।

पेपर लीक से छात्रों का भविष्य प्रभावित : हिमांशु जायसवाल

हिमांशु जायसवाल ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उनका आरोप है कि विद्यार्थी वर्षों तक कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की कमी उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। उन्होंने नीट परीक्षा में पेपर लीक से प्रभावित छात्रों को उचित मुआवजा देने तथा परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

शिक्षा में व्यापक सुधार की जरूरत : सुरेंद्र गुप्ता

विश्वविद्यालय अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता ने कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है। यदि समय रहते इसमें व्यापक सुधार नहीं किए गए तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर पड़ेगा। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और युवाओं के लिए बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

सरकार तक पहुंचाए जाएंगे छात्रों के सुझाव

युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 'छात्रों की गूंज' अभियान के माध्यम से छात्रों की समस्याओं और सुझावों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। संगठन ने पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने और छात्र हितों की रक्षा की मांग दोहराई। साथ ही कहा कि इन मुद्दों को लेकर भविष्य में भी जनजागरण और संवाद अभियान जारी रहेगा। कार्यक्रम में गौतम गुप्ता, आयुष गुप्ता, प्रमोद जायसवाल, सत्यम यादव, वैभव पांडेय सहित युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

किरायेदार का पुलिस सत्यापन नहीं कराया तो अब होगी कार्रवाई

सरगुजा पुलिस सख्त : गांधीनगर में मकान मालिक गिरफ्तार किरायेदारों ने की थी डकैती और आर्म्स एक्ट की वारदात

डीआईजी-एसएसपी राजेश अग्रवाल बोले- ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध,हर मकान मालिक कराए किरायेदार का वेरिफिकेशन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

बाहरी राज्यों से आए किरायेदारों के सत्यापन को लेकर लगातार अभियान चला रही सरगुजा पुलिस अब नियमों की अनदेखी करने वाले मकान मालिकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेगी। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी मकान मालिक बिना पुलिस सत्यापन के किरायेदार नहीं रखे। नियमों का उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में थाना गांधीनगर क्षेत्र के एक मकान मालिक को किरायेदारों की जानकारी पुलिस को नहीं देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, जिला दंडाधिकारी के आदेश के बावजूद गांधीनगर क्षेत्र के सरगंवा गैस गोदाम के पास रहने वाले राहुल विश्वकर्मा ने अपने मकान में किरायेदार रखे, लेकिन उनकी जानकारी और सत्यापन संबंधित थाने में जमा नहीं कराया। बाद में इन्हीं किरायेदारों पर 13 मई 2026 की रात घंघरी-गेरवानी नाला के पास डकैती और आर्म्स एक्ट के गंभीर मामले में शामिल होने का आरोप सामने आया। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आने पर पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई अन्य मकान मालिकों के लिए भी स्पष्ट संदेश है कि किरायेदारों का सत्यापन कराना कानूनी जिम्मेदारी है।

लगातार चल रहा सत्यापन अभियान : सरगुजा पुलिस पिछले कई दिनों से जिलेभर में किरायेदारों और मुसाफिरों के सत्यापन का विशेष अभियान चला रही है। पहले चरण में 125 मकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में 450 लोगों का सत्यापन किया गया था। इसके बाद दूसरे चरण में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के 350 मकानों में करीब 750 लोगों का भौतिक सत्यापन किया गया। पुलिस टीम लगातार संदिग्ध व्यक्तियों, किरायेदारों और बाहरी राज्यों से आए लोगों की जांच कर रही है।

अब घर बैठे भी करा सकते हैं पुलिस वेरिफिकेशन

पुलिस ने बताया कि किरायेदार सत्यापन की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल भी हो गई है। मकान मालिक 'समाधान' ऐप या सीसीटीएनएस नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित थाना में जाकर ऑफलाइन सत्यापन कराने की सुविधा भी उपलब्ध है।

लंबित मांगों को लेकर डाक कर्मचारियों का चरणबद्ध आंदोलन,18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

20 जुलाई से काली पट्टी बांधकर करेंगे काम,28 जुलाई को धरना; बढ़ते कार्यभार और लंबित मांगों को लेकर जताई नाराजगी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

भारतीय डाक कर्मचारी संघ (ग्रुप-सी),सरगुजा संभाग ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। इस संबंध में संघ ने अधीक्षक डाकघर,सरगुजा संभाग को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की औपचारिक सूचना दी है। संगठन का कहना है कि यदि समय रहते मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को क्रमशः तेज करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। घोषित कार्यक्रम के अनुसार डाक कर्मचारी 20 से 27 जुलाई तक काली पट्टी बांधकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इसके बाद 28 जुलाई को भोजनावकाश के दौरान संभागीय कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। यदि इसके बाद भी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 6 अगस्त को एक दिवसीय हड़ताल की जाएगी, जबकि 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

बढ़ते कार्यभार पर जताई नाराजगी

संघ का कहना है कि लंबे समय से डाक कर्मचारियों से विभिन्न प्रकार के लक्ष्य (टारगेट) पूरे कराने के साथ-साथ अतिरिक्त कार्य भी कराए जा रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि बढ़ते कार्यभार और अनावश्यक दबाव के कारण मानसिक तनाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे कार्य परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनती जा रही हैं। उनका कहना है कि इन समस्याओं को लेकर कई बार विभाग का ध्यान आकर्षित किया गया,लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला।

सूरजपुर पुलिस में नेतृत्व परिवर्तन : डीआईजी/एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर को भावभीनी विदाई, एसपी योगेश कुमार पटेल का आत्मीय स्वागत

-संवाददाता-
सूरजपुर,18 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
पुलिस विभाग में नेतृत्व परिवर्तन के अवसर पर शुक्रवार को विश्रामपुर स्थित ऑफिसर्स क्लब में गरिमामय विदाई एवं स्वागत समारोह आयोजित किया गया, पुलिस मुख्यालय रायपुर स्थानांतरित हुए डीआईजी/एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर (भापुसे) को पुलिस परिवार,जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भावभीनी विदाई दी। वहीं जिले के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल (भापुसे) का आत्मीय स्वागत करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी गईं। समारोह में पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर प्रशांत कुमार ठाकुर के कार्यकाल को यादगार बताया गया।

प्रशांत कुमार ठाकुर के कार्यकाल को बताया अनुकरणीय

समारोह में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि श्री ठाकुर ने अपने कार्यकाल में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ जनविश्वास को मजबूत बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए,अपराध नियंत्रण,सामुदायिक पुलिसिंग,साइबर अपराधों की रोकथाम, नशा मुक्ति जनजागरूकता अभियान और टीम भावना के साथ कार्य करने की उनकी कार्यशैली को सभी ने सराहा,अधिकारियों ने कहा कि उनका कार्यकाल सूरजपुर पुलिस के लिए प्रेरणादायी रहा है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नेतृत्व क्षमता की सराहना की...

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल ने कहा कि प्रशांत कुमार ठाकुर ने अपने कार्यकाल में समर्पण,अनुशासन और दूरदर्शिता का परिचय दिया,उन्होंने केवल कानून-व्यवस्था को मजबूत नहीं किया बल्कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास का मजबूत सेतु भी स्थापित किया, उनका सहज,सरल और प्रेरणादायी व्यक्तित्व पुलिस बल के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी के लिए प्रेरणा बना रहेगा, उन्होंने नई जिम्मेदारी में भी निरंतर सफलता की शुभकामनाएं दीं।

कलेक्टर रेना जमील ने बेहतर समन्वय को बताया सफलता की कुंजी

कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस के बीच उत्कृष्ट समन्वय के कारण जिले में कानून-व्यवस्था,जनकल्याण और विकास कार्यों को नई गति मिली,उन्होंने कहा कि प्रशांत कुमार ठाकुर का नेतृत्व प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावी रहा और उनके कार्यकाल में कई जनहितकारी पहल सफलतापूर्वक संचालित हुईं, उन्होंने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

नवपदस्थ एसपी योगेश कुमार पटेल ने आगे बढ़ाने का दिलाया भरोसा

नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने कहा कि प्रशांत कुमार ठाकुर के नेतृत्व में सूरजपुर पुलिस ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, उन्होंने कहा कि अनुशासित कार्यशैली, प्रभावी पुलिसिंग और जनता के विश्वास को मजबूत करने की जो परंपरा स्थापित हुई है,उसे वे पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाएंगे,उन्होंने श्री ठाकुर के उत्तम स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

अन्य अधिकारियों ने भी व्यक्त किए विचार

कार्यक्रम को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजेन्द्र सिंह पाटले तथा वनमंडलाधिकारी डी.पी. साहू ने भी संबोधित किया,दोनों अधिकारियों ने प्रशांत कुमार ठाकुर के प्रशासनिक अनुभव,कार्यकुशलता और टीम भावना की सराहना करते हुए उनके नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दीं,कार्यक्रम का संचालन निरीक्षक जावेद मियादाद ने किया।

विदाई भाषण में बोले प्रशांत कुमार ठाकुर...सूरजपुर का स्नेह हमेशा रहेगा याद

विदाई संबोधन में डीआईजी/एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने कहा कि सूरजपुर में मिला स्नेह,विश्वास और सहयोग उनके लिए सदैव अविस्मरणीय रहेगा, उन्होंने कहा कि जिले में कार्यकाल के दौरान प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी ने पूरी निष्ठा, ईमानदारी और टीम भावना के साथ कार्य किया,जिसके परिणामस्वरूप कानून-व्यवस्था को मजबूत करने,अपराध नियंत्रण,सामुदायिक पुलिसिंग, साइबर अपराधों की रोकथाम तथा नशा मुक्ति जनजागरूकता अभियान जैसी अनेक जनहितकारी पहलों को सफलतापूर्वक संचालित किया जा सका,उन्होंने कहा कि सूरजपुर पुलिस की सबसे बड़ी ताकत उसकी टीम भावना है,इसी सामूहिक प्रयास से जनता का पुलिस पर विश्वास लगातार मजबूत हुआ है,उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी संवेदनशीलता, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ जनसेवा करते रहने का संदेश दिया।

बड़ी संख्या में अधिकारी एवं पुलिसकर्मी रहे मौजूद

समारोह में डीआईजी/एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर की धर्मपत्नी एवं पुत्र सहित एसडीएम शिवानी जायसवाल,चांदनी कंवर,ललिता भगत,अजय कोसाम,सीएसपी बेनार्ड कुजूर,डीएसपी मुख्यालय महालक्ष्मी कुलदीप,एसडीओपी राजेश जोशी,अनूप एक्का,अभिषेक पैंकरा,सभी थाना एवं चौकी प्रभारी,जिला पुलिस कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी तथा जिला प्रशासन के अनेक अधिकारी उपस्थित रहे,पूरे समारोह के दौरान भावनात्मक माहौल रहा और सभी ने प्रशांत कुमार ठाकुर के योगदान को याद करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

महुआ की गंध से गांव पहुंचा हाथी,150 मीटर दौड़ाकर ग्रामीण को पटक-पटककर मार डाला

राजपुर वन परिक्षेत्र के रेवतपुर नवापारा में दर्दनाक घटना,तीन माह से क्षेत्र में सक्रिय चार हाथियों के दल से दहशत,वन विभाग ने जारी की सतर्कता

-संवाददाता-
राजपुर,18 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के रेवतपुर नवापारा गांव में शुक्रवार रात जंगली हाथी के हमले में एक ग्रामीण की दर्दनाक मौत हो गई। महुआ की गंध से आकर्षित होकर हाथी गांव में घुस आया और मकान के पीछे रखे महुआ तक पहुंच गया। जान बचाने के लिए घर से बाहर भागे ग्रामीण को हाथी ने करीब 150 मीटर तक दौड़ाया और सूंड़ से उठाकर पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर हाथी प्रभावित इलाकों में बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष की गंभीर तस्वीर सामने ला दी है। वन विभाग के अनुसार राजपुर वन परिक्षेत्र के उप परिक्षेत्र बरियों के रेवतपुर वन कक्ष क्रमांक पी-2556 में पिछले तीन-चार माह से चार जंगली हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा है। विभाग इनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए था,लेकिन शुक्रवार रात करीब नौ बजे दल से अलग होकर एक हाथी रेवतपुर नवापारा गांव में पहुंच गया।

महुआ की गंध बनी हादसे की वजह : हाथी गांव निवासी बालमसाय टेकाम के घर के पीछे पहुंचा,जहां महुआ रखा हुआ था। महुआ की तेज गंध से आकर्षित होकर हाथी ने मकान के पिछले हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया। उस समय घर के भीतर बालमसाय टेकाम, उनकी पत्नी नागमती बाई, बेटा और छोटी बच्ची मौजूद थे। हाथी की आहट मिलते ही परिवार में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग और हाथी मित्र दल को सूचना दी,जिसके बाद वन अमला मौके पर पहुंचकर परिवार को सुरक्षित निकालने में जुट गया।

अंधेरा और बारिश ने बढ़ाया खतरा : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात करीब साढ़े नौ बजे बालमसाय टेकाम जान बचाने के लिए घर से निकलकर सड़क की ओर भागे। उस समय हल्की बारिश और घना अंधेरा होने के कारण वे सुरक्षित स्थान तक नहीं पहुंच सके। हाथी ने उनका पीछा किया और करीब 150 मीटर तक दौड़ाने के बाद सूंड़ से उठाकर कई बार पटक दिया। गंभीर चोटों के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद हाथी वापस जंगल की ओर लौट गया। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पंचनामा कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया और परिजनों को सौंप दिया गया। वन विभाग ने वन्य प्राणी जनहानि का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

परिजनों को तत्काल सहायता,शेष मुआवजा प्रक्रिया में...

वन विभाग ने मृतक की पत्नी नागमती बाई को तत्काल राहत के रूप में 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। अधिकारियों ने बताया कि नियमानुसार औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शेष 5 लाख 75 हजार रुपये की मुआवजा राशि भी प्रदान की जाएगी।

महुआ,आम और कटहल खींच रहे हाथियों को गांवों तक...

वन अधिकारियों के अनुसार बरसात के मौसम में गांवों के आसपास महुआ, आम, कटहल और अन्य खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के कारण हाथी आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। राजपुर वन परिक्षेत्र के कई गांवों में पिछले कुछ महीनों से हाथियों की नियमित आवाजाही दर्ज की गई है। इसे देखते हुए वन विभाग हाथी मित्र दल के सहयोग से लगातार निगरानी, मुनादी और जनजागरूकता अभियान चला रहा है।

बाबा बच्छराज कुंवर धाम की नदी में मिला 22 वर्षीय युवक का शव,मौत से फैली सनसनी

दो दिन से लापता था युवक,मोटरसाइकिल पहले मिली और बाद में नदी में मिला शव,पुलिस हर पहलू से कर रही जांच

-संवाददाता-
बलरामपुर,18 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
जिले के चलगली थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध बाबा बच्छराज कुंवर धाम में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब धाम के पास बहने वाली नदी में एक 22 वर्षीय युवक का शव तैरता हुआ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों की जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान विमलेश वर्मा (22 वर्ष) निवासी कछिया के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विमलेश धाम में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ावे में दिए जाने वाले बकरों की बली काटने का कार्य करता था। परिजनों के मुताबिक वह पिछले दो दिनों से लापता था और उसकी लगातार तलाश की जा रही थी।

मोटरसाइकिल पहले मिली, फिर नदी में मिला शव : घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि युवक की मोटरसाइकिल पहले श्रद्धालुओं के पास मिली थी, जबकि उसका शव बाद में नदी में तैरता मिला। इस घटनाक्रम के बाद मौत को लेकर तरह-तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।

घटनास्थल पर जुटी भीड़, पुलिस ने जुटाए साक्ष्य : शव मिलने की खबर फैलते ही बाबा बच्छराज कुंवर धाम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु पहुंच गए। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ भी की।

परिजनों ने की निष्पक्ष जांच की मांग : मृतक के चाचा संतकल्प ने बताया कि विमलेश दो दिनों से घर नहीं लौटा था। परिवार के लोग उसकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि धाम के पास नदी में एक शव मिला है। मौके पर पहुंचने पर शव की पहचान विमलेश के रूप में हुई। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने और यदि किसी की संलिप्तता हो तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई : पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और परिजनों सहित अन्य लोगों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।

रविंद्र भारती बने भाजयुमो के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला प्रभारी

-संवाददाता-
सूरजपुर,18 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव एवं प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी की सहमति से भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिहा ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के संभाग प्रभारियों एवं जिला प्रभारियों की घोषणा की है, इस घोषणा के तहत रविंद्र भारती को बिलासपुर संभाग के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है। रविंद्र भारती संगठन में लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, उन्होंने पूर्व में सूरजपुर जिले के लटोरी मंडल अध्यक्ष तथा भारतीय जनता युवा मोर्चा के सूरजपुर जिला अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है,वर्तमान में वे भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश खेल एवं कला प्रमुख के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं,रविंद्र भारती का राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति से प्रारंभ हुआ, उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) में इकाई अध्यक्ष,प्रदेश कार्यसमिति सदस्य तथा सूरजपुर जिले के प्रथम जिला संयोजक सहित कई महत्वपूर्ण दायित्व निभाए, छात्र संगठन से लेकर युवा मोर्चा तक उन्होंने संगठन विस्तार, युवा नेतृत्व निर्माण और विभिन्न संगठनात्मक अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई, संगठन में उनकी सक्रियता, कार्यशैली और लंबे अनुभव को देखते हुए उन्हें यह नई जिम्मेदारी सौंपी गई है,उनकी नियुक्ति पर भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है तथा विश्वास जताया है कि उनके नेतृत्व में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी, वहीं रविंद्र भारती ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने जिस विश्वास के साथ उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है,उस पर पूरी निष्ठा,समर्पण और कार्यकर्ता भावना के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे।

पूजा पैकरा आत्महत्या प्रकरण : दोषियों की गिरफ्तारी में देरी पर जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर उठा सवाल

सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष विजय सिंह बोले...केवल मुआवजा नहीं, दोषियों की गिरफ्तारी और न्याय भी सुनिश्चित करें जनप्रतिनिधि

-संवाददाता-
बैकुंठपुर,18 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
पूजा पैकरा आत्महत्या प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी में हो रही देरी को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने एक बार फिर अपनी नाराजगी जाहिर की है,सर्व आदिवासी समाज, जिला कोरिया के जिलाध्यक्ष विजय सिंह ने कहा कि इस मामले में अब तक केवल एक नामजद आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जबकि अन्य नामजद आरोपी अभी भी गिरफ्तारी से बाहर बताए जा रहे हैं, इसे लेकर समाज में असंतोष और चिंता का माहौल है, विजय सिंह ने कहा कि समाज का आरोप है कि शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के बावजूद कुछ अन्य लोगों को भी आरोपी के रूप में नामजद नहीं किया गया है, ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष और प्रभावी जांच को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि जांच के दौरान सामने आने वाले सभी तथ्यों पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए।

जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर सवाल

विजय सिंह ने इस मामले में जिले के प्रभारी मंत्री,क्षेत्रीय विधायक,जिले की अन्य विधायक,जिला पंचायत अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए,उन्होंने कहा कि यह समझ से परे है कि इतने गंभीर मामले में जनप्रतिनिधियों

की सक्रिय भूमिका क्यों दिखाई नहीं दे रही है, उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी केवल पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता या मुआवजा दिलाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए,बल्कि दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी उन्हें आगे आना चाहिए।

मुआवजा पर्याप्त नहीं,न्याय जरूरी

विजय सिंह का कहना है कि आर्थिक सहायता पीड़ित परिवार के लिए राहत का माध्यम हो सकती है,लेकिन वास्तविक न्याय तभी होगा जब मामले में शामिल सभी दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई हो और उन्हें कानून के दायरे में लाया जाए, उन्होंने कहा कि यदि आरोपी खुलेआम घूमते रहें और जांच अधूरी रह जाए, तो इससे आम लोगों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास कमजोर पड़ता है।

सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग...

सर्व आदिवासी समाज ने मांग की है कि मामले में फरार सभी नामजद आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, साथ ही यदि शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अन्य व्यक्तियों की भूमिका सामने आती है,तो उनके विरुद्ध भी निष्पक्ष जांच कर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।

लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगा आंदोलन

विजय सिंह ने कहा कि आदिवासी समाज इस मामले में न्याय की मांग को लेकर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाता रहेगा, उन्होंने कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं होती,तब तक समाज का संघर्ष जारी रहेगा।

एक स्टार की दौड़ में क्या सुपर कॉप प्रधान आरक्षक 105 से सीधे 60 के अंदर आना चाहता है?

वरिष्ठता सूची जारी होते ही शुरू हुआ 'गणित', पुलिस महकमे में चर्चाओं का बाजार गर्म

370 प्रधान आरक्षक,करीब 60 पद, 15 वेटिंग... और हर कोई अपने नंबर का हिसाब लगाने में जुटा

सरगुजा रेंज में एएसआई पदोन्नति सूची जारी,370 में से 201 प्रधान आरक्षक योग्य,169 अयोग्य घोषित

जशपुर में सबसे अधिक 46,जबकि सूरजपुर में 44 कर्मचारी अयोग्य,सीमित पदों के बीच पदोन्नति की दौड़ तेज

स्थानांतरण से बचने वाले कर्मचारियों की भी चर्चा,पदोन्नति सूची ने बढ़ाई हलचल

अंतिम फैसला नियमों का होगा,लेकिन विभागीय गलियारों में संभावनाओं पर खूब हो रही चर्चा

-संवाददाता-
अंबिकापुर/एमसीबी 18 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा रेंज में प्रधान आरक्षक से सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) पदोन्नति के लिए वर्ष 2026 की संयुक्त वरिष्ठता सह उपयुक्तता सूची जारी होने के बाद पुलिस महकमे का माहौल अचानक बदल गया है, वर्दी पर लगने वाला एक स्टार हमेशा से सम्मान,जिम्मेदारी और अधिकार का प्रतीक माना जाता रहा है,यही वजह है कि सूची जारी होते ही पूरे रेंज में चर्चा का विषय अब अपराध नियंत्रण नहीं,बल्कि पदोन्नति का गणित बन गया है,चाय की मेज से लेकर थाना परिसर तक एक ही सवाल तैर रहा है इस बार स्टार किसके कंधे पर चमकेगा? सूत्रों के अनुसार सूची में लगभग 370 प्रधान आरक्षकों के नाम हैं, जबकि वर्तमान रिक्तियों के आधार पर करीब 60 पदोन्नतियां और लगभग 15 कर्मचारियों को प्रतीक्षा सूची में स्थान मिलने की संभावना बताई जा रही है, ऐसे में स्वाभाविक है कि सूची में पीछे मौजूद कर्मचारियों की नजरें अब केवल अपने क्रमांक पर नहीं, बल्कि पूरी सूची पर टिकी हुई हैं।

बता दे की सरगुजा रेंज में प्रधान आरक्षक से सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) पदोन्नति के लिए वर्ष 2026 की संयुक्त वरिष्ठता सह उपयुक्तता सूची जारी होने के साथ ही पूरे पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है,सूची में कुल 370 प्रधान आरक्षकों को शामिल किया गया है, इनमें 201 को योग्य तथा 169 को विभिन्न कारणों से अयोग्य घोषित किया गया है, सूची में सेवा अभिलेख, सेवा मूल्यांकन,अनुशासनात्मक रिकॉर्ड और अन्य विभागीय मापदंडों के आधार पर पात्रता का उल्लेख किया गया है,विभागीय स्तर पर चर्चा है कि रिक्त पद सीमित होने के कारण इस बार प्रतिस्पर्धा पहले की तुलना में अधिक है,इसी वजह से वरिष्ठता सूची जारी होने के बाद कई कर्मचारी अपने संभावित क्रम,उपलब्ध रिक्तियों और पदोन्नति की संभावना का लगातार आकलन कर रहे हैं।

वरिष्ठता सूची नहीं,मानो गणित की किताब बन गई हो-विभागीय सूत्र बताते हैं कि वरिष्ठता सूची जारी होने के बाद कई कर्मचारी केवल अपना क्रम देखकर शांत हो गए, लेकिन कुछ लोग पूरी सूची का पन्ना-दर-पन्ना अध्ययन कर रहे हैं,कौन से कर्मचारी सेवानिवृत्ति के करीब हैं,कौन पदोन्नति लेकर दूसरे जिले नहीं जाना चाहता,किसके व्यक्तिगत कारण हैं और यदि कोई पदोन्नति स्वीकार नहीं करता तो अगला क्रम किसका बनेगा–ऐसी चर्चाएं महकमे में लगातार सुनाई दे रही हैं, एक प्रधान आरक्षक ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि सूची जारी होने के बाद कई कर्मचारियों ने अपने संभावित अवसरों का स्वयं आकलन शुरू कर दिया है, यह असामान्य नहीं है,क्योंकि हर पदोन्नति सूची के साथ ऐसी गणनाएं होती हैं, कंधे पर स्टार लगाना है जिसके लिए दिमाग भी चाहिए,षड्यंत्र भी चाहिए,पहुंच भी चाहिए और जो संभव हो सकता है वह भी करेंगे,कुछ इसी दिशा में बढ़ रहा हैं, सुपर कॉप प्रधान आरक्षक जिनका नाम 105 नंबर पर है,वह सीधे 60 के अंदर आना चाहता है या फिर 75 के अंदर उन्होंने जो दिमाग लगाया है,वह अच्छे-अच्छे लोग शायद ना लगा पाए,बता दें कि प्रधान आरक्षक से एएसाआई में पदोन्नति होने के लिए सूची तैयार हो गई है, जिसमें 370 लोग शामिल है और 60 लोगों का चयन होना है 15 वेटिंग में जा सकते हैं, या टोटल 75 का चयन होंगा,सुपर कॉप प्रधान आरक्षक 105 नंबर पर है इसलिए उसका नाम इस बार की पदोन्नति सूची में नहीं आ सकता क्योंकि सूची में 45 अंक नीचे हैं,पर वह 45 अंकों का उछाल चाह रहे हैं इसीलिए वह संभाग में जितने भी प्रधान आरक्षक है जो सेवानिवृत होने वाले हैं जो जिला छोड़कर स्थानांतरण के दडर से प्रमोशन नहीं लेना चाहते हैं उनके घर जा जाकर आवेदन लिखवा रहा है।

योग्य से अधिक चर्चा अयोग्य कर्मचारियों की- जारी सूची में बड़ी संख्या में ऐसे प्रधान आरक्षक भी हैं जिन्हें विभिन्न कारणों से पदोन्नति के लिए अयोग्य माना गया है,दस्तावेज के अनुसार किसी कर्मचारी को सेवा अभिलेख में निर्धारित अंक प्राप्त नहीं होने,पिछले पांच वर्षों में बड़ी सजा मिलने,सेवा मूल्यांकन में कम अंक,सजा एवं इनाम का अनुपात प्रतिकूल होने अथवा अन्य विभागीय कारणों के चलते अपात्र घोषित किया गया है। कई प्रविष्टियों में अयोग्यता का कारण स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है।

जशपुर में सबसे अधिक अयोग्य-आंकड़ों के अनुसार जशपुर जिले में 77 कर्मचारियों में से 46 अयोग्य घोषित किए गए हैं,जो पूरी रेंज में सर्वाधिक है, इसके बाद सूरजपुर में 44 और सरगुजा में 37 कर्मचारी अयोग्य पाए गए। वहीं पीटीएस मैनपाट के सभी छह कर्मचारी योग्य घोषित हुए हैं।

स्थानांतरण भी बना बड़ा कारण

पुलिस विभाग में पदोन्नति का मतलब कई बार नया जिला भी होता है, लंबे समय से एक जिले में कार्यरत कुछ कर्मचारी पारिवारिक,सामाजिक या अन्य कारणों से स्थानांतरण नहीं चाहते। ऐसे में विभाग के भीतर यह चर्चा रहती है कि कुछ कर्मचारी पदोन्नति लेने के बजाय वर्तमान पद पर ही बने रहना पसंद करते हैं,सूत्रों का कहना है कि वरिष्ठता सूची जारी होने के बाद ऐसे कर्मचारियों की संख्या और उनके संभावित निर्णयों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं, हालांकि कौन कर्मचारी पदोन्नति लेगा और कौन नहीं, इसका निर्णय पूरी तरह व्यक्तिगत और विभागीय प्रक्रिया के अधीन होता है।

महकमे में चर्चाओं का दौर

विभागीय गलियारों में इन दिनों सबसे अधिक चर्चा इसी बात की है कि वरिष्ठता सूची में ऊपर मौजूद कुछ कर्मचारी यदि किसी कारणवश पदोन्नति स्वीकार नहीं करते हैं,तो क्रमशः नीचे के पात्र कर्मचारियों को अवसर मिल सकता है, इसी संभावना को लेकर तरह-तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं,हालांकि इन चर्चाओं की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अंतिम निर्णय केवल नियमों,उपलब्ध रिक्तियों और विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर ही लिया जाता है।

एक स्टार का आकर्षण क्यों इतना बड़ा?

पुलिस सेवा में एएसआई पद पर पदोन्नति केवल वेतन वृद्धि का विषय नहीं होती, इसके साथ जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, निर्णय लेने की भूमिका मजबूत होती है और सेवा अभिलेख में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है,यही कारण है कि हर प्रधान आरक्षक अपने करियर में इस पड़ाव तक पहुंचना चाहता है,सेवानिवृत्ति से पहले यदि किसी कर्मचारी के कंधे पर एक स्टार लग जाता है तो इसे उसके लंबे सेवाकाल की बड़ी उपलब्धि माना जाता है,यही वजह है कि पदोन्नति सूची जारी होने के बाद महकमे में उत्सुकता चरम पर रहती है।

रिक्त पद सीमित...प्रतिस्पर्धा ज्यादा...

सूत्रों के अनुसार एएसआई के रिक्त पद सीमित हैं,ऐसे में सूची में योग्य घोषित होना पदोन्नति की पहली शर्त है,लेकिन अंतिम चयन रिक्त पदों,वरिष्ठता क्रम,विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद ही होगा,इस कारण योग्य सूची में शामिल कर्मचारियों के बीच भी प्रतिस्पर्धा बनी हुई है।

अयोग्यता के कारणों पर भी उठ रहे सवाल

सूची जारी होने के बाद कई कर्मचारी अपने सेवा अभिलेख और सेवा मूल्यांकन की समीक्षा करने में जुट गए हैं,जिन कर्मचारियों को सेवा अभिलेख में कम अंक,सेवा मूल्यांकन में कमी अथवा दंड संबंधी कारणों से अयोग्य घोषित किया गया है, उनके बीच भी विभागीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, कुछ कर्मचारी विभागीय नियमों के तहत उपलब्ध वैधानिक उपायों पर भी विचार कर रहे हैं।

नियम क्या कहते हैं?-

पुलिस विभाग के जानकारों के अनुसार केवल वरिष्ठता ही पदोन्नति का आधार नहीं होती,सेवा अभिलेख, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन,अनुशासनात्मक रिकॉर्ड,दंड-पुण्य का विवरण तथा विभागीय नियमों के अनुसार उपयुक्तता का परीक्षण भी किया जाता है,यदि कोई कर्मचारी स्वेच्छा से पदोन्नति स्वीकार नहीं करता है या नियमानुसार उसका नाम विचार से बाहर हो जाता है,तभी क्रम के अनुसार अगले पात्र कर्मचारी पर विचार किया जाता है,इसलिए किसी भी प्रकार की चर्चा या अटकल से अधिक महत्व विभागीय प्रक्रिया और सक्षम अधिकारियों के निर्णय का होता है।

सरगुजा रेंज एएसआई पदोन्नति सूची (2026)-जिलेवार स्थिति

जिला	कुल	योग्य	अयोग्य
सरगुजा	76	39	37
सूरजपुर	99	55	44
बलरामपुर	56	42	14
कोरिया	25	13	12
जशपुर	77	31	46
एमसीबी	31	15	16
पीटीएस मैनपाट	6	6	0

सूची ने बढ़ाई उत्सुकता

सूची जारी होने के बाद जहां योग्य घोषित कर्मचारियों में उत्साह है,वहीं कुछ कर्मचारी अपने सेवा अभिलेखों का पुनर्मूल्यांकन कराने या आवश्यक अभ्यावेदन देने की तैयारी में हैं। दूसरी ओर पुलिस महकमे में पदोन्नति के संभावित समीकरणों को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है,कई कर्मचारियों का मानना है कि अंतिम सूची जारी होने तक अनेक तरह की संभावनाएं बनती और बदलती रहती हैं,इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

आखिरकार फैसला नियमों का ही होगा...

पुलिस महकमे में चर्चाएं, अनुमान और संभावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन अंतिम पदोन्नति सूची विभागीय नियमों, वरिष्ठता, उपयुक्तता और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर ही तय होगी, वरिष्ठता सूची ने जरूर पूरे रेंज में हलचल पैदा कर दी है, लेकिन कंधे पर स्टार आखिर किसके चमकेंगे, इसका जवाब केवल अंतिम आदेश आने के बाद ही मिलेगा, फिलहाल इतना तय है कि सरगुजा रेंज में इस समय सबसे अधिक चर्चा किसी बड़े अपराध की नहीं, बल्कि 'एक स्टार' की है–और यह चर्चा तब तक जारी रहने वाली है, जब तक अंतिम पदोन्नति आदेश जारी नहीं हो जाता।

अब अंतिम आदेश का इंतजार...

फिलहाल संयुक्त वरिष्ठता सह उपयुक्तता सूची जारी होने के बाद पदोन्नति प्रक्रिया का पहला चरण पूरा माना जा रहा है, अब अंतिम निर्णय विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा, उपलब्ध रिक्त पदों तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद जारी होने वाले पदोन्नति आदेश से होगा, ऐसे में पूरे सरगुजा रेंज के पुलिस महकमे की निगाहें अब अंतिम सूची और पदोन्नति आदेश पर टिकी हुई हैं।

एक नजर में...

- कुल प्रधान आरक्षक: 370
- पदोन्नति के लिए योग्य: 201
- अयोग्य घोषित: 169
- सबसे अधिक योग्य: सूरजपुर (55)
- सबसे अधिक अयोग्य: जशपुर (46)
- पीटीएस मैनपाट: सभी 6 कर्मचारी योग्य घोषित हुए।

इंडेक्स

- 370 प्रधान आरक्षकों की संयुक्त वरिष्ठता सह उपयुक्तता सूची जारी।
- 201 कर्मचारी पदोन्नति के लिए योग्य, 169 अयोग्य घोषित।
- जशपुर में सबसे अधिक 46, जबकि सूरजपुर में 44 कर्मचारी अयोग्य पाए गए।
- सेवा अभिलेख, सेवा मूल्यांकन, बड़ी सजा, सजा-इनाम तथा निर्धारित अंक नहीं मिलने जैसे कारणों से कई कर्मचारी अयोग्य घोषित किए गए।
- अब अंतिम फैसला विभागीय पदोन्नति समिति एवं रिक्त पदों के आधार पर होगा।

पूजा पैकरा को न्याय दिलाने सड़क पर उतरा सर्व आदिवासी समाज...घड़ी चौक पर श्रद्धांजलि सभा,मोमबत्ती जलाकर दी श्रद्धांजलि

-संवाददाता-
बैकुंठपुर,18 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

पूजा पैकरा आत्महत्या प्रकरण को लेकर अब सर्व आदिवासी समाज न्याय की मांग को लेकर खुलकर सामने आ गया है,सर्व आदिवासी समाज जिला कोरिया के तत्वावधान में जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के घड़ी चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया,जहां बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने एकत्र होकर स्वर्गीय पूजा पैकरा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर और दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की,श्रद्धांजलि सभा के दौरान समाज के पदाधिकारियों और उपस्थित लोगों ने पूजा पैकरा के परिजनों को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि समाज अपनी बेटी के साथ हुए घटनाक्रम को लेकर गंभीर है और मामले में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई चाहता है। इस अवसर पर कांग्रेस अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ जिला कोरिया के अध्यक्ष विजय सिंह ने कहा कि आदिवासी समाज की बेटी को न्याय दिलाना समाज की प्राथमिक मांग है, उन्होंने कहा कि सर्व आदिवासी समाज दिवंगत पूजा पैकरा और उसके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए पूरी मजबूती से खड़ा है, उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में अब भी कई आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिससे समाज में आक्रोश व्याप्त है,उन्होंने शासन और प्रशासन से मांग की कि फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, सभा में मौजूद समाज के लोगों ने कहा कि यह केवल एक परिवार का मामला नहीं,बल्कि पूरे समाज की अस्मिता और न्याय से जुड़ा विषय है, उन्होंने निष्पक्ष एवं त्वरित जांच के साथ दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई,श्रद्धांजलि सभा में रविंद्र सिंह, विजय सिंह ठाकुर,मनियार सिंह,विश्वास भगत,जितेंद्र पैकरा,आर.एस. चांदे,रविशंकर राजवाड़े सहित सर्व आदिवासी समाज के अनेक पदाधिकारी, पुरुष एवं महिला सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभा का समापन दिवंगत पूजा पैकरा की आत्मा की शांति की प्रार्थना और न्याय की मांग के संकल्प के साथ हुआ।

CMYK

सोनहत वन विभाग का 'डबल गेम'? पहले चंदन चोरी, अब तालाब निर्माण पर सवाल, क्या दोनों मामलों की होगी निष्पक्ष जांच?

नर्सरी से बेशकीमती चंदन के पेड़ों की चोरी का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा,अब 'कागजी तालाब' निर्माण को लेकर उठे नए आरोप जनसंगठनों ने उच्च स्तरीय जांच और भौतिक सत्यापन की मांग उठाई...

-राजन पाण्डेय-

सोनहत/कोरिया,18 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सोनहत वन परिक्षेत्र एक बार फिर गंभीर आरोपों के कारण चर्चा में है, पहले सरकारी नर्सरी से बेशकीमती चंदन के पेड़ों की चोरी का मामला सामने आया और अब तालाब निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं तथा मशीनों के उपयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं,स्थानीय लोगों और जनसंगठनों का कहना है कि यदि पहले मामले में समय पर प्रभावी कार्रवाई हुई होती तो शायद आज दूसरा विवाद सामने नहीं आता,क्षेत्र में चर्चा इस बात की है कि क्या चंदन चोरी की तरह तालाब निर्माण से जुड़े आरोपों की भी केवल औपचारिक जांच होगी या इस बार जिम्मेदारों तक कार्रवाई पहुंचेगी,हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और विभाग की ओर से भी विस्तृत पक्ष सामने आना बाकी है।

चंदन चोरी का मामला बना अविश्वास की वजह

कुछ समय पहले सोनहत मुख्यालय स्थित वन विभाग की सरकारी नर्सरी से बेशकीमती चंदन के पेड़ों की चोरी का मामला सामने आया था। उस समय यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी थी, भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) ने इस मामले में ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की थी,स्थानीय लोगों का कहना है कि समय बीतने के बावजूद मामले में कोई ऐसी कार्रवाई सामने नहीं आई जिससे यह भरोसा बन सके कि जिम्मेदारों तक जांच पहुंची है,इसी कारण अब तालाब निर्माण से जुड़े नए आरोप सामने आने पर लोगों का भरोसा और कमजोर होता दिखाई दे रहा है।

अब तालाब निर्माण पर उठ रहे हैं सवाल

वन विभाग द्वारा जंगल क्षेत्र में जल संरक्षण के उद्देश्य से कई तालाब बनाए जाने का दावा किया गया है,लेकिन स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि अधिकांश स्थानों पर तालाब की जगह केवल गड्ढे खोदे गए हैं,उनका कहना है कि न तो कई स्थानों पर निर्धारित मापदंडों का पालन दिखाई देता है और न ही मजबूत मेड़ तथा जल संरक्षण की आवश्यक संरचनाएं विकसित की गई हैं,आरोप यह भी है कि निर्माण कार्य मजदूरों की बजाय जेसीबी और ट्रैक्टर जैसी मशीनों से कराया गया, यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तो यह केवल निर्माण गुणवत्ता का मामला नहीं रहेगा,बल्कि सरकारी राशि के उपयोग और रोजगार के अवसरों पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करेगा।

15 जून के बाद मिट्टी कार्य पर भी सवाल

स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि 15 जून के बाद भी मिट्टी संबंधी कार्य जारी रहे, जबकि सामान्यतः मानसून अवधि में ऐसे कार्यों पर प्रतिबंध रहता है,यदि यह तथ्य जांच में सही पाया जाता है तो यह नियमों के पालन और प्रशासनिक निगरानी दोनों पर सवाल खड़े करेगा।

सूचना पटल नहीं लगाए जाने पर भी आपत्ति

जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जिन स्थानों पर निर्माण कार्य हुए वहां अधिकांश जगहों पर सूचना पटल (डिस्प्ले बोर्ड) नहीं लगाए गए, सूचना पटल नहीं होने से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य किस योजना से स्वीकृत हुआ, कुल लागत कितनी थी,कार्य एजेंसी कौन थी,तकनीकी स्वीकृति किस अधिकारी ने दी,स्थानीय लोगों का कहना है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह जानकारी सार्वजनिक होना आवश्यक है।

स्थानीय वन समिति को भी जानकारी नहीं?-आरोप यह भी लगाया गया है कि स्थानीय वन समिति के पदाधिकारियों को निर्माण कार्यों की जानकारी नहीं दी गई,यदि समिति को विश्वास में लिए बिना कार्य हुए हैं तो यह सहभागिता आधारित वन प्रबंधन की भावना के विपरीत माना जा रहा है।

जन सहयोग समिति ने उठाए गंभीर प्रश्न- कोरिया जन सहयोग समिति के उपाध्यक्ष राजू साहू और पुष्पेंद्र राजवाड़े ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि चंदन चोरी जैसे गंभीर मामले में जिम्मेदारी तय नहीं हो सकी तो तालाब निर्माण की शिकायतों में भी निष्पक्ष जांच को लेकर लोगों के मन में संदेह स्वाभाविक है,उन्होंने मांग की है कि केवल कागजी जांच नहीं बल्कि सभी निर्माण स्थलों का भौतिक सत्यापन कराया जाए तथा स्वीकृत राशि, तकनीकी मापदंड और वास्तविक कार्य का मिलान किया जाए।

उच्च स्तरीय जांच की मांग-स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि दोनों मामलों–चंदन चोरी और तालाब निर्माण–की स्वतंत्र एवं उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, उनका कहना है कि जांच में निम्न बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए चंदन चोरी मामले की वर्तमान स्थिति, तालाब निर्माण की तकनीकी गुणवत्ता,स्वीकृत एवं व्यय राशि का मिलान, मशीनों के उपयोग की वैधता,मजदूरों को रोजगार क्यों नहीं मिला,निर्माण कार्य की समय-सीमा और नियमों का पालन।

आंदोलन की चेतावनी

कोरिया जन सहयोग समिति ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र निष्पक्ष जांच शुरू नहीं की गई और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों, मजदूरों और युवाओं के साथ आंदोलन किया जाएगा,समिति का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं बल्कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

अब नजर विभाग की कार्रवाई पर...

लगातार दो विवादों ने सोनहत वन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, एक ओर चंदन चोरी का मामला अभी तक लोगों के मन से नहीं निकला है,वहीं दूसरी ओर तालाब निर्माण को लेकर उठे आरोपों ने विभाग की जवाबदेही पर नई बहस शुरू कर दी है,अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वन विभाग इन आरोपों पर पारदर्शी और निष्पक्ष जांच कराकर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करेगा,या फिर यह मामला भी पूर्व की तरह केवल फाइलों तक सीमित रह जाएगा, जांच के बाद ही इन आरोपों की सत्यता और जिम्मेदारी स्पष्ट हो सकेगी।

आईआईटी दिल्ली बूट कैंप के लिए पीएम श्री ईएमआरएस पोड़ीडीह के 10 विद्यार्थियों का चयन,क्षेत्र में खुशी की लहर

छत्तीसगढ़ के चयनित पांच एकलव्य विद्यालयों में शामिल हुआ पोड़ीडीह, छात्र-छात्राएं राष्ट्रीय स्तर पर सीखेंगे विज्ञान और नवाचार

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां,18 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और आधुनिक तकनीकी ज्ञान से जोड़ने की दिशा में पीएम श्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) पोड़ीडीह ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, आईआईटी दिल्ली द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित आईआईटी दिल्ली बूट कैंप में भाग लेने के लिए विद्यालय के 10 विद्यार्थियों का चयन हुआ है, इस उपलब्धि से विद्यालय ही नहीं, बल्कि पूरे खड़गवां क्षेत्र और एमसीबी जिले में खुशी का माहौल है। जानकारी के अनुसार, जनजातीय विद्यार्थियों के लिए आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर के बूट कैंप में छत्तीसगढ़ से केवल पांच एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का चयन किया गया है, इनमें विकासखंड खड़गवां स्थित पीएम श्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पोड़ीडीह का चयन होना विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता और विद्यार्थियों की प्रतिभा का प्रमाण माना जा रहा है, विद्यालय से 5 छात्र एवं 5 छात्राओं सहित कुल 10 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। चयनित विद्यार्थियों में अरविंद कुमार टोप्पो, अभय कुमार पैकरा, आदित्य प्रताप सिंह, दिलीप कुमार भरकाम, आयुष कुमार सिंह, सरोज सिंह, लता सिंह, आकांक्षा सिंह, पूजा सिंह एवं पिंकी सिंह शामिल हैं, चयनित छात्र-छात्राएं आईआईटी दिल्ली में आयोजित बूट कैंप के दौरान विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शोध एवं आधुनिक शिक्षण गतिविधियों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे, इस प्रशिक्षण का उद्देश्य जनजातीय विद्यार्थियों को देश के प्रमुख तकनीकी संस्थान के शैक्षणिक वातावरण से परिचित कराना तथा उनमें वैज्ञानिक सोच और नवाचार की भावना विकसित करना है, विद्यार्थियों के साथ एस्कॉर्ट शिक्षक के रूप में सुश्री अर्चना ठाकुर (टीजीटी विज्ञान) एवं श्री कादिर अली (पीजीटी अंग्रेजी) को भी भेजा गया है,जो पूरे प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। विद्यालय के प्राचार्य श्री अरुण कुमार पाठा एवं आदिम जाति विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने चयनित विद्यार्थियों एवं एस्कॉर्ट शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें औपचारिक रूप से आईआईटी दिल्ली बूट कैंप के लिए रवाना किया,इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह अवसर विद्यार्थियों के लिए सीखने और भविष्य में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का महत्वपूर्ण माध्यम साबित होगा।

बारिश के गंदे पानी में खेलते दिखे छात्रावास के बच्चे,सुरक्षा व्यवस्था पर उठा गंभीर सवाल

लकड़ापारा छात्रावास में जलभराव के बीच बच्चों की मस्ती का वीडियो चर्चा में...ग्रामीणों ने अधीक्षक की रात्रिकालीन अनुपस्थिति का लगाया आरोप

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां,18 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

विकासखंड खड़गवां के लकड़ापारा छात्रावास से सामने आई तस्वीरों और वीडियो ने छात्रावास की सुरक्षा एवं प्रबंधन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, बारिश के बाद छात्रावास परिसर में गंदा पानी भर गया, जिसमें कई बच्चे खेलते और मस्ती करते नजर आए। इस दृश्य ने बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और छात्रावास की निगरानी व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि छात्रावास के अधीक्षक रात्रिकालीन समय में छात्रावास में उपस्थित नहीं रहते, जिसके कारण बच्चों की देखरेख प्रभावी ढंग से नहीं हो पाती, ग्रामीणों का कहना है कि यह स्थिति नई नहीं है, बल्कि लंबे समय से छात्रावास का संचालन इसी तरह किया जा रहा है, यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह छात्रावास संचालन से जुड़े नियमों के पालन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

गंदे पानी में खेलते बच्चे,स्वास्थ्य पर मंडराया खतरा-बारिश के बाद परिसर में जमा गंदे पानी में बच्चों के खेलने से संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, ऐसे जलभराव वाले स्थानों पर मच्छरों का

प्रजनन तेजी से होता है,जिससे डेंगू,मलेरिया जैसी बीमारियों का जोखिम बढ़ता है,इसके अलावा त्वचा संबंधी संक्रमण, डायरिया और अन्य जलजनित रोगों की आशंका भी बनी रहती है,ऐसे में सवाल उठता है कि बच्चों को इन खतरों से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है।

निगरानी व्यवस्था पर उठे सवाल-ग्रामीणों का कहना है कि यदि छात्रावास में जिम्मेदार अधिकारी या अधीक्षक नियमित रूप से मौजूद रहें,तो बच्चों को इस तरह जोखिम भरी परिस्थितियों में खेलने से रोका जा सकता है। उनका आरोप है कि निगरानी के अभाव में बच्चे बिना रोक-टोक परिसर में इधर-उधर घूमते और जलभराव वाले स्थानों पर खेलते रहते हैं।

बच्चों की सुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंता-छात्रावासों की स्थापना का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण,अनुशासित जीवन और बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है,यदि परिसर में स्वच्छता, सुरक्षा और निगरानी जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं में लापरवाही बरती जाती है,तो इसका सीधा असर बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य पर पड़ सकता है,इसलिए विशेषज्ञ भी छात्रावासों में नियमित निगरानी और साफ-सफाई को अत्यंत आवश्यक मानते हैं।

प्रशासन से उठे कई सवाल...

इस घटना के बाद स्थानीय स्तर पर कई सवाल उठ रहे हैं क्या छात्रावास में अधीक्षक की रात्रिकालीन उपस्थिति की जांच होगी? क्या शिक्षा विभाग और आदिम जाति विकास विभाग पूरे मामले की जांच कराएंगे? बारिश के पानी की निकासी और परिसर की साफ-सफाई की उचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई? बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

ग्रामीणों ने की जांच की मांग...

ग्रामीणों ने छात्रावास की निष्पक्ष जांच कराने, अधीक्षक की उपस्थिति का सत्यापन करने तथा परिसर में जलनिकासी और सुरक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग की है,उनका कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक सुधार नहीं किए गए तो भविष्य में कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है, हालांकि,अधीक्षक या संबंधित विभाग का पक्ष समाचार लिखे जाने तक प्राप्त नहीं हो सका, उनका पक्ष मिलने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई का समर्थन,पंजीकृत बीएएमएस चिकित्सकों की साख बचाने की मांग

भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ ने सरगुजा कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन,कहा...जालसाजों पर सख्ती हो, लेकिन योग्य चिकित्सकों की छवि न हो धूमिल

-संवाददाता-

कोरिया,18 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

जिले में फर्जी और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान का भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ, जिला कोरिया ने समर्थन किया है,साथ ही प्रकोष्ठ ने मांग की है कि कार्रवाई के दौरान विधिवत पंजीकृत आयुष (बीएएमएस) चिकित्सकों की छवि और सम्मान प्रभावित नहीं होना चाहिए, इसी मांग को लेकर भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रतिनिधिमंडल ने सरगुजा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में जिला संयोजक डॉ. भुवन भास्कर साहू,डॉ. अमित कुमार पाण्डेय,डॉ. दीपक सोनी,डॉ. शुभम गुप्ता सहित अन्य चिकित्सक शामिल रहे,ज्ञापन में चिकित्सकों ने कहा कि फर्जी डिग्री के आधार पर चिकित्सा करने वाले और बिना अनुमति क्लीनिक संचालित करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जनहित में आवश्यक है और यह अभियान लगातार जारी रहना चाहिए। हालांकि उन्होंने हाल के दिनों में कुछ समाचारों में 'बीएएमएस डॉक्टर अवैध क्लीनिक चला रहे थे' जैसे सामान्य शब्दों के प्रयोग पर आपत्ति जताई, उनका कहना है कि संबंधित आरोपी कोई पंजीकृत बीएएमएस चिकित्सक नहीं था, बल्कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर काम कर रहा था। ऐसे मामलों में पूरे बीएएमएस समुदाय को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है, चिकित्सकों ने प्रशासन को छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की 11 फरवरी 2019 की अधिसूचना का भी हवाला दिया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 के तहत विधिवत पंजीकृत बीएएमएस चिकित्सकों को अधिसूचना में वर्णित एलोपैथिक दवाओं के उपयोग तथा प्राथमिक एवं आपातकालीन उपचार की वैधानिक अनुमति प्राप्त है,इसलिए निरीक्षण और कार्रवाई के दौरान इस कानूनी प्रावधान का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से मांग की कि फर्जी डॉक्टरों और फर्जी डिग्री धारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी जाए, लेकिन पंजीकृत बीएएमएस चिकित्सकों की सामाजिक प्रतिष्ठा और वैधानिक अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित की जाए। साथ ही प्रशासन और मीडिया से तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर ही सूचनाएं जारी करने का आग्रह किया गया, ताकि योग्य चिकित्सकों की छवि प्रभावित न हो और आम जनता का विश्वास बना रहे, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ का कहना है कि उनका उद्देश्य फर्जी चिकित्सकों पर रोक लगाने के साथ-साथ वर्षों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे पंजीकृत आयुष चिकित्सकों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करना भी है, ज्ञापन को स्वास्थ्य व्यवस्था में पारदर्शिता और जिम्मेदार कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

CMYK

टोहनी के चक्कर...

गानावाला चैनल पर टोहनी के चक्कर कॉमेडी वीडियो रिलीज हो गया है,यूट्यूब पर गानावाला चैनल की लोकप्रियता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। हाल ही में इस चैनल द्वारा जारी गानों में लाखों व्यूज़ पार कर सुपरहिट साबित हुआ है। अब चैनल हरियाणवी और भोजपुरी गानों के जरिए अपनी पहुंच को और विस्तार देने जा रहा है। मनोरंजन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्षेत्रीय भाषाओं के गानों की मांग लगातार बढ़ रही है। खासकर हरियाणवी और भोजपुरी गानों को बड़े पैमाने पर दर्शक सुनते और देखते हैं। ऐसे में गानावाला चैनल का यह कदम न केवल व्यावसायिक दृष्टि से फायदेमंद होगा,बल्कि भारतीय लोक संगीत को भी नई ऊंचाई देगा। गानावाला यूट्यूब चैनल सिर्फ गाने ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित वीडियो एलबम और शॉर्ट फिल्मों को भी रिलीज़ करने की योजना बना रहा है। चैनल प्रबंधन ने बताया कि वे देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर स्थानीय कलाकारों को मंच देंगे और उनकी प्रतिभा को दुनिया तक पहुंचाएंगे।

40 सालों से बॉलीवुड पर कर रहा है राज मोहनलाल का कंटेंट

भूल भुलैया,दृश्यम के बाद अब हैवान रचेगी इतिहास!

मोहनलाल न केवल भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं बल्कि वह बॉलीवुड रीमेक के पीछे सबसे बड़ी प्रेरणाओं में से भी एक हैं। जिनकी कई हिट फिल्मों के रीमेक हिंदी में बने हैं और सफल भी रहे हैं। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने साउथ सिनेमा में अपनी बेहतरीन अदाकारी से एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ साउथ तक ही सीमित है। उनकी सुपरहिट फिल्मों के रीमेक के जरिए वे हिंदी सिनेमा में भी खूब लोकप्रिय हैं।

हैवान भी मोहनलाल की फिल्म की रीमेक

मोहनलाल की कई फिल्मों के रीमेक हिंदी में बने और हिट भी रहे। दृश्यम इसका जीता जागता उदाहरण है। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की अपकमिंग हैवान भी मोहनलाल की ओप्पम की रीमेक है जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कॉमेडी, साइको थ्रिलर से लेकर फैमिली एंटरटेनर और क्राइम थ्रिलर तक मोहनलाल की फिल्मोग्राफी ने चार दशकों से अधिक समय तक हिंदी सिनेमा को प्रभावित किया है और शायद आगे भी करती रहेगी।

इन सितारों ने बटोरीं सुर्खियां

फिल्मों ने सफलता पाई ही साथ ही इन फिल्मों में लीड रोल निभाने वाले हीरो भी सुर्खियां बटोर ले गए। जिनमें अक्षय कुमार,सलमान खान,अजय देवगन ,जैकी श्रॉफ,गोविंदा,सुनील शेट्टी,मिथुन चक्रवर्ती,जीतेंद्र,भाग्यश्री,चंकी पांडे,अक्षय खन्ना, अरविंद स्वामी और कई अन्य शामिल हैं।

हैवान पर टिकीं है सबकी निगाहें

अब सबकी निगाहें हैवान पर हैं, क्या प्रियदर्शन अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ हिंदी में ओप्पम का जादू फिर से बना सकते हैं? खैर इस सवाल का जवाब तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही मिलेगा लेकिन इतना तो तय है कि अक्षय और सैफ के लुक ने फिल्म के लिए दर्शकों की बेसब्री और बढ़ा दी है।

वृंदा मास्टर का बड़ा बयान : रश्मिका मंदाना की मेहनत ने बनाया उन्हें सुपरस्टार

पॉपुलर डांस कोरियोग्राफर ब्रिंदा मास्टर,जो अब डायरेक्टर रवींद्र पुले की बेसब्री से इंतज़ार की जा रही एक्शन एंटरटेनर माइसा के लिए एक गाना कोरियोग्राफ कर रही हैं, ने शनिवार को फिल्म की लीड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की उनके काम के प्रति कमिटमेंट के लिए

तारीफ की। रश्मिका मंदाना की तारीफ करते हुए अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट लिखते हुए,ब्रिंदा ने लिखा,माइसा के एक गाने पर काम करके बहुत खुश हूँ। रिहर्सल से लेकर शूट तक,आपने गाने के लिए जितनी प्रैक्टिस और तैयारी की है,वह सच में कमाल की है। उन्होंने आगे कहा,आपका कमिटमेंट आपकी सफलता की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। इतने सालों से इंडस्ट्री में होने के बाद,मैं ईमानदारी से कह सकती हूँ कि मैंने शायद ही कभी इतनी मेहनत,डिसिप्लिन और डेडिकेशन वाली एक्ट्रेस देखी हो। ब्रिंडा ने लिखा,मैं चाहे कोई भी करेक्शन दूं,आप हमेशा उसे मुस्कुराते हुए लेते हैं और तुरंत उस पर काम करते हैं। जब आप दर्द में होते हैं,तब भी आपका फोकस कभी नहीं बदलता और आप और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। मुझे यकीन है कि ऑडियंस इस फिल्म में आपकी मेहनत देखेगी। मायसा के रिलीज़ होने और दुनिया को स्क्रीन पर आपके बनाए जादू को देखने का इंतज़ार नहीं कर सकती। उन्होंने आगे कहा,और ये कुछ प्यारे लोग थे जिन्होंने बहुत मेहनत की और यह सब मुमकिन बनाया। आप लोगों का शुक्रिया और मैं जल्द ही सेट पर फिर मिलूंगी। यूनिट के करीबी सूत्रों ने पहले बताया था कि स्टंट मास्टर केचा खांपकडी ने इस फिल्म के लिए कुछ हाई वोल्टेज एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफ किए थे, जिन्हें इस शेड्यूल में शूट किया गया था। माना जाता है कि रश्मिका ने इस शेड्यूल के दौरान फिल्म के मुख्य एक्टर्स के साथ कुछ हाई इंटेंसिटी एक्शन सीक्वेंस किए थे। एक्ट्रेस इस एक्शन शेड्यूल के दौरान फिल्माए जाने वाले सीक्वेंस में परफॉर्म करने के लिए बैंकॉक, थाईलैंड में एक इंटेंसिव स्टंट और कॉम्बैट बूटकैंप में कड़ी ट्रेनिंग ले रही थीं।

प्रियंका-निक की क्यूट बॉन्डिंग : बाबू नाम सुनकर फिदा हुए जोनास ब्रदर्स

जोनास ब्रदर्स के पॉडकास्ट के हालिया एपिसोड में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का अपने पति निक जोनास के लिए इस्तेमाल किया गया प्यारा निकनेम चर्चा का विषय बन गया। केविन और जो जोनास ने जब प्रियंका को निक के लिए बाबू शब्द का इस्तेमाल करते सुना,तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस कपल की बॉन्डिंग और यह प्यारा नाम बहुत पसंद आया। पॉडकास्ट के एक मज़ेदार रैपिड फायर सेगमेंट के दौरान,भाइयों ने निक से प्रियंका की उन चीज़ों के बारे में सवाल पूछे जो उन्हें निक और उनके रिश्ते में सबसे ज़्यादा पसंद हैं, जिससे कई दिलचस्प बातें सामने आईं। घर पर अपनी बॉन्डिंग के बारे में बात करते हुए,निक ने बताया कि जब भी प्रियंका उन्हें बाबू कहकर बुलाती हैं, तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि उन्हें उनकी मदद की जरूरत है। प्रियंका ने आगे कहा कि घर पर हर काम के लिए उन्हें निक की ज़रूरत पड़ती है। प्रियंका ने मज़ाक में कहा,जब निक घर पर होते हैं तो मेरे हाथ काम नहीं करते। बस बाबू की आवाज़ आती है। इस पर निक ने कहा, जब मैं यह सुनता हूँ, तो मैं कहता हूँ, हाँ। रोज़मर्रा की स्थितियों की नकल करते हुए प्रियंका ने कहा,बाबू, रिमोट काम नहीं कर रहा है।बाबू, इंटरनेट नहीं चल रहा है। क्या मुझे ड्रिंक मिल सकती है,प्लीज़? इस बातचीत पर केविन और जो अपनी हँसी नहीं रोक पाए और बोले,ओह, हमें यह बहुत पसंद आया। यह बहुत बढ़िया है। हर किसी का अपना अंदाज़ होता है। हमें यह पसंद है। इसे देखना अच्छा लगता है। प्रियंका ने प्यार से जवाब दिया, हाँ। मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आई लव यू, निक।

गुड पर्सनॉलिटी की अहमियत पर सपना चौधरी का प्रेरणादायक पोस्ट

मशहूर डांसर और अभिनेत्री सपना चौधरी अपनी शानदार डांसिंग स्टाइल और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। सपना अक्सर अपने फैंस के साथ अपनी जिंदगी से जुड़े खास पल साझा करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने एक ऐसा पोस्ट शेयर किया, जिसमें

उन्होंने खूबसूरती से ज्यादा अच्छे व्यक्तित्व और स्वभाव को महत्व दिया। सपना चौधरी ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वह सड़क पर बेहद खुश और बेफिक्र अंदाज में घूमती नजर आ रही हैं। वीडियो में उनका कैजुअल और मस्ती भरा अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। हालांकि वीडियो से ज्यादा चर्चा उनके द्वारा लिखे गए संदेश की हो रही है। वीडियो शेयर करते हुए सपना चौधरी ने लिखा, सुंदरता तो सिर्फ लोगों का ध्यान खींचती है, लेकिन इंसान का अच्छा चरित्र हमेशा के लिए दिल जीत लेता है। अपने इस संदेश के जरिए उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति की असली पहचान उसकी बाहरी सुंदरता से नहीं बल्कि उसके व्यवहार, सोच और स्वभाव से होती है। सपना चौधरी के इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। फैंस उनके विचारों की तारीफ कर रहे हैं और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा कि खूबसूरती समय के साथ बदल सकती है, लेकिन अच्छा व्यवहार और अच्छा दिल हमेशा लोगों के बीच अपनी जगह बनाए रखता है।

सपना चौधरी लंबे समय से मनोरंजन जगत में सक्रिय हैं। हरियाणवी डांस से अपनी पहचान बनाने वाली सपना ने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। छोटे मंचों से शुरुआत करने वाली सपना आज देशभर में लोकप्रिय नाम बन चुकी हैं। उनकी लोकप्रियता सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों में उनके लाखों प्रशंसक हैं। सपना चौधरी ने अपने डांस और स्टेज परफॉर्मेंस के जरिए अलग पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने टीवी रियलिटी शो और फिल्मों में भी काम किया। उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा मानी जाती है।

खेल समाचार

जापान ओपन के फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु

ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनीं

पीवी सिंधु ने चीन की वर्ल्ड नंबर-4 चैन युफेई के चोटिल होकर हटने के बाद जापान ओपन सुपर 750 के फाइनल में एंट्री कर लिया है...मैच के वक्त सिंधु 21-19, 15-10 से आगे चल रही थीं... इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत सिंधु अब वर्ल्ड रैंकिंग में 9वें स्थान पर पहुंच गई हैं...

टोक्यो,18 जुलाई 2026। पीवी सिंधु शनिवार को जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। चीन की दुनिया की नंबर 4 खिलाड़ी चैन युफेई सेमीफाइनल के बीच में ही चोट के कारण हट गई, जिसके बाद भारतीय स्टार खिलाड़ी को इस सीजन के पहले फाइनल का टिकट मिल गया। सिंधु मैच में पूरी तरह हावी नजर आईं और वह 21-19, 15-10 से आगे चल रही थीं, तभी पूर्व ओलंपिक चैंपियन चैन को हैमस्ट्रिंग की संभावित चोट के कारण हटना पड़ा। बता दें कि जापान ओपन की फाइनल में पहुंचे वाली वह पहली महिला खिलाड़ी बनी हैं।

शुरुआत से ही पीवी सिंधु का दबदबा

इससे पहले पीवी सिंधु ने मजबूत शुरुआत की और अपने आक्रामक खेल और तेज मूवमेंट से पहले गेम के बीच में चार अंकों की बढ़त बना ली। चैन ने वापसी करते हुए स्कोर 19-19 से बराबर किया, लेकिन सिंधु ने आखिरी पलों में संयम बनाए रखा और अपने पहले गेम प्वाइंट को भुनाते हुए पहला गेम 21-19 से जीत लिया। दूसरे गेम में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पीवी सिंधु ने शुरुआत से ही रैलियों पर दबदबा बनाए रखा और तेजी से 15-10 की बढ़त बना ली। इसके बाद चैन युफेई चोट से जूझती नजर आईं और उन्होंने आखिर में मैच से हटने का फैसला लिया। यह जीत सिंधु के 2026 में शानदार

वापसी अभियान का एक और अहम पड़ाव है। उनके हटते ही सिंधु की जीत हो गई और वह फाइनल में पहुंच गई हैं।

सिंधु की रैंकिंग में हुआ सुधार

31 साल की पीवी सिंधु ने साल की शुरुआत वर्ल्ड नंबर 18 रैंकिंग के साथ की थी, लेकिन लगातार बेहतर प्रदर्शन के दम पर उन्होंने अपनी रैंकिंग में सुधार किया और अब वह दुनिया की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। यह उनकी बेहतरीन फॉर्म में वापसी का साफ संकेत है। जापान ओपन का खिताब जीतने के लक्ष्य के साथ सिंधु रविवार को होने वाले फाइनल में जापान की अकाने यामागुची या इंडोनेशिया की कुसुम वरदानी में से किसी एक का सामना करेंगी। इससे पहले, शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल मैच से ठीक पहले जापान की नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद सिंधु जापान ओपन सुपर 750 के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची थीं। 2023 में डेनमार्क ओपन के बाद सुपर 750 टूर्नामेंट में सिंधु का यह पहला सेमीफाइनल था। इस सीजन में वह तीन सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं।

गोल्ड जीतने को तैयार आशी चौकसे

नई दिल्ली,18 जुलाई 2026। हांग्जो एशियाई खेलों में तीन मेडल जीतकर कॉन्टिनेंटल लेवल पर अपनी पहचान बनाने के तीन साल बाद, भारत की राइफल शूटर आशी चौकसे एक बार फिर भारत की मेडल की उम्मीदों के साथ उसी चीनी शहर लौट रही हैं। इस बार वह आईएसएसएफ वर्ल्ड कप (राइफल/ पिस्टल/ शॉटगन) में हिस्सा लेंगी और उनकी नज़र इस साल के आखिर में होने वाले आइची-नागोया एशियाई खेलों के लिए मोमेंटम बनाने पर होगी। भारतीय राइफल और पिस्टल टीम शुक्रवार रात आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 के लिए हांग्जो रवाना हुई, जहां चौकसे महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में हिस्सा लेंगी। उसी शहर में 2023 एशियाई खेलों में दो सिल्वर और एक व्यक्तिगत ब्रॉन्ज़ मेडल जीतने वाली 24 वर्षीय खिलाड़ी भारत की सबसे बड़ी मेडल

उम्मीदों में से एक होंगी,क्योंकि वह उस प्रदर्शन को दोहराने या उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगी। टीम के रवाना होने से पहले नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया द्वारा आयोजित मीडिया डे के दौरान बात करते हुए, चौकसे ने कहा कि व्यस्त इंटरनेशनल सीज़न की तैयारी अच्छी चल रही है।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल अर्जेंटीना और स्पेन की भिड़ंत आज

मुंबई,18 जुलाई 2026। फुटबॉल प्रेमियों के लिए साल का सबसे बड़ा मुकाबला सामने है। हफ्तों तक चले रोमांचक मुकाबलों,शानदार गोल,उलटफेर भरे नतीजों और यादगार पलों के बाद अब 2026 फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल प्रशंसकों की नजर इस ऐतिहासिक मुकाबले पर टिकी हुई है। फाइनल मुकाबला ईस्ट रदरफोर्ड, न्यू जर्सी स्थित न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच रविवार, 19 जुलाई को शाम 7 बजे से शुरू होगा। अर्जेंटीना और स्पेन दोनों ही टीमें शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताबी मुकाबले तक पहुंची हैं। टूर्नामेंट के दौरान दोनों टीमों ने अपनी रणनीति, खिलाड़ियों की प्रतिभा और दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। अब दोनों देशों के प्रशंसक अपनी-अपनी टीम को विश्व चैंपियन बनते देखने का इंतजार कर रहे हैं। अर्जेंटीना के लिए यह मुकाबला खास महत्व रखता है। टीम पहले भी विश्व कप की बड़ी सफलताओं

का हिस्सा रही है और एक बार फिर खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। दूसरी ओर, स्पेन अपनी तकनीकी शैली,शानदार पासिंग गेम और युवा प्रतिभाओं के दम पर ट्रॉफी पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगा। फाइनल मुकाबले को लेकर दुनिया भर में उत्साह चरम पर है। भारत में भी फुटबॉल प्रशंसकों ने इस खास रात के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। खासकर मुंबई जैसे महानगर में लोग घर से बाहर निकलकर दोस्तों और परिवार के साथ बड़े पर्दे पर मैच देखने की योजना बना रहे हैं। मुंबई में कई रेस्टोरेंट, बार और अन्य स्थानों पर फीफा वर्ल्ड कप फाइनल की लाइव स्क्रीनिंग आयोजित की जा रही है। यहां प्रशंसकों को बड़े स्क्रीन पर मैच देखने के साथ-साथ विशेष मैच-नाइट मेन्यू, थीम आधारित सजावट और फुटबॉल जैसा माहौल देने की तैयारी की गई है। जो लोग घर पर मैच देखने के बजाय किसी सार्वजनिक स्थान पर फुटबॉल का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए मुंबई में कई विकल्प मौजूद हैं। कई जगहों पर प्रशंसकों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं, जहां वे अपनी पसंदीदा टीम का समर्थन करते हुए मैच का लुत्फ उठा सकेंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर भी मैच की लाइव स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जा रही है। यात्रियों और फुटबॉल प्रेमियों के लिए यह एक खास अनुभव होगा, जहां वे यात्रा के दौरान भी इस ऐतिहासिक मुकाबले से जुड़े रह सकेंगे। फुटबॉल फाइनल की रात को लेकर रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। कई स्थानों पर फुटबॉल थीम वाले कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि दर्शकों को स्टेडियम जैसा अनुभव दिया जा सके।

नाम परिवर्तन सूचना

प्रारूप-(एक)

मैं,फलोरा खलको (PHALORA XALXO) पत्नी एडविन खलखो, गाँव / शहर - कन्या परिसर, बिसुनपुर,राघवपुरी, तहसील-अंबिकापुर, जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़ 497001 ने अपना नाम फलोरा खलको (PHALORA XALXO) से बदल कर फ्लोरा खलखो (FLORA XALXO) रख लिया है तथा अपने पति का उपनाम हिंदी अक्षर में 'खलको' के स्थान पर शुद्ध रूप में 'खलखो' अंगीकार कर लिया है।

आवेदक
फलोरा खलको
बिसुनपुर,राघवपुरी,अंबिकापुर, जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान, जिला-सूरजपुर,छ0ग0

रा.प्र.क्र./ब-121
ग्राम - प0ह0न0-08

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक हरकुलाल पिता समय लाल जाति गोड़ निवासी ग्राम शिवप्रसाद नगर प.ह.न. 08 रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पुत्री सुमन सिंह का जन्म दिनांक 25/02/2005 को ग्राम शिव प्रसाद नगर में हुई है, अज्ञानतावश जन्म पंजीयन नही करा पाया है। आवेदक अपने पुत्री सुमन सिंह का जन्म पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत शिवप्रसाद नगर को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 20/07/2026 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।
आज दिनांक 30.06.2026 का मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

सील **कार्यपालिक दण्डाधिकारी**
भैयाथान-जिला-सूरजपुर

छत्तीसगढ़ शासन,जल संसाधन विभाग
कार्यालय कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग क्र.1,अम्बिकापुर जिला - सरगुजा (छ.ग.)

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना

eProcurement Portal:https://eproc.cgstate.gov.in

(द्वितीय आमंत्रण)

निविदा सूचना क्रमांक - 03/वं.ले.लि./2026-27 दिनांक 15.07.2026 निम्नलिखित कार्यों के लिये दिनांक 03.08.2026 (17.30 बजे) तक ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है :-

स.क्र.	सिस्टम निविदा क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत
	195449	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र -1 अम्बिकापुर कार्यालय का जीर्णोद्वार कार्य ।	रू0 378.35 लाख । (जी.एस.टी. छोडकर)

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 22.07.2026 समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड किये जा सकते है।

नोटः- निविदा मे भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित/पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है ।

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग क्र. 1, अम्बिकापुर
(छ.ग.) कृते - मुख्य अभियंता
हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग
अंबिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

जी0नं0 -262702193/5

CMYK

अविश्वास प्रस्ताव पर सीएम साय का पलटवार...

बोले...यह सरकार नहीं,जनता के जनादेश के खिलाफ विधानसभा में ढाई साल की उपलब्धियां गिनाईं....

रायपुर,18 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आक्रामक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रदेश की तीन करोड़ जनता के विश्वास और जनादेश का अपमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों में जनता ने भाजपा और विकास की राजनीति पर भरोसा जताया है।

विपक्ष जनता के फैसले पर सवाल उठा रहा : सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पहले यह बताए कि उसका अविश्वास आखिर किस पर है 25 लाख किसानों पर, जिन्हें 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का लाभ मिला, 70 लाख महिलाओं पर जिन्हें महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने एक हजार रुपये मिल रहे हैं, या उन प्रदेशवासियों पर जिन्होंने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया।

किसानों और महिलाओं के लिए योजनाएं गिनाईं

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, दो साल का बकाया बोनस और शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण जैसी सुविधाएं दी हैं। वहीं महतारी वंदन योजना के तहत लगभग 70 लाख महिलाओं को 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई है। उन्होंने बताया कि 10.40 लाख से अधिक महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाया गया है।

आदिवासी और गरीबों के लिए कई फैसले

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज के लिए तेंदूपत्ता पारिश्रमिक में वृद्धि, चरणपादुका योजना, वनाधिकार लाभ, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनमन योजना के जरिए विकास कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

कानून व्यवस्था और नक्सल मोर्चे पर उपलब्धियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की गई है। रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है और साइबर अपराध रोकने के लिए नए साइबर थाने खोले जा रहे हैं।

निवेश और रोजगार पर जोर...

मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक नीति के तहत राज्य को 8.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे लाखों रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर,आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है।

ऊर्जा,डिजिटल सेवाएं और सुशासन

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 76 हजार से अधिक घरों में सोलर प्लांट लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना से 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राहत मिली है। उन्होंने बताया कि सेवा सेतु के माध्यम से 36 विभागों की 528 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं और 435 प्रशासनिक सुधार लागू किए गए हैं।

विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प दोहराया

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनता का विश्वास सरकार के साथ है और विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी।

बिलासपुर में 93 साल का रिकॉर्ड टूटा,भारी बारिश का अलर्ट

बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत

रायपुर,18 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में मानसून फिर एक्टिव हो गया है। बंगाल,झारखंड और ओडिशा में बने लो प्रेशर एरिया से प्रदेश में लगातार नमी पहुंच रही है। इसी वजह से पिछले 24 घंटे में मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। बिलासपुर ने 93 साल बाद ऐसी बारिश देखी,जिसने पूरे शहर की रफ्तार थाम दी। महज 24 घंटे में 415.6 मिमी (16 इंच से ज्यादा) बारिश ने 1933 का 14.93 इंच का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सड़कों पर कमर तक पानी भर गया, सैकड़ों घर जलमग्न हो गए और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए SDRF को मोटर बोट उतारनी पड़ी। रेलवे ट्रैक, हाईवे और पुल पानी में डूबने से रेल और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। एक महिला की डूबने से मौत हो गई। स्कूल बंद रहे और परीक्षाएं प्रभावित हुईं। रेलवे स्टेशन और यार्ड में पानी भरने से 7 ट्रेनें रद्द करनी पड़ीं और 4 ट्रेनों का मार्ग बदला गया। करीब 80 बसों का संचालन भी प्रभावित रहा। सरगुजा जिले में बारिश के दौरान बिजली गिरने से 4 बच्चे झुलस गए। इनमें से 2 बच्चों की मौत हो गई। 2 बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दोनों सगे भाई हैं। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। जांजगीर-चांपा के अकलतरा स्थित कर्रा नाला जलाशय का बांध भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया। गेट के पास दरार आने के बाद पानी का तेज बहाव शुरू हो गया। प्रशासन ने 125 लोगों को सुरक्षित राहत शिविरों में पहुंचाया है। 18 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, 1 जून से अब तक पूरे प्रदेश में औसतन 307.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो पिछले 10 सालों के आज तक के रिकॉर्ड (375.4 मिमी) का 81.8 प्रतिशत है। आज राज्य में औसतन 17.7 मिमी बारिश दर्ज की गई है। इस सीजन में बिलासपुर संभाग के जिलों में मानसूनी बादल सबसे ज्यादा मेहरबान रहे हैं। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला पूरे प्रदेश में टॉप पर है, जहां अब तक 525.4 मिमी बारिश हो चुकी है, जो इसकी औसत का 178.7% है। इसके बाद जांजगीर-चांपा में 441.5 मिमी (आज 53.3 मिमी) और बिलासपुर जिला 383.7 मिमी बारिश दर्ज कर चुका है, जहां आज सबसे ज्यादा 58.6 मिमी पानी बरसा।

कैग रिपोर्ट : पंचायत व्यवस्था पर सवाल

61% पद खाली,3243 करोड़ का दावा

रायपुर,18 जुलाई 2026। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नवीनतम रिपोर्ट ने छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन की वित्तीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कैग की यह रिपोर्ट राज्य में जमीनी स्तर पर विकास कार्यों के क्रियान्वयन, प्रशासनिक दक्षता और वित्तीय अनुशासन की पोल खोलती है। रिपोर्ट के अनुसार,पंचायतों में भारी कर्मचारी कमी,समय पर फंड न मिलना और निगरानी तंत्र का पूरी तरह विफल होना राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा बन गया है। यह रिपोर्ट प्रशासनिक गलियारों में हलचल पैदा करने के साथ ही भविष्य के लिए एक कड़ी चेतावनी भी है।

61% रिक्त पदों से ठप पड़ा प्रशासनिक कामकाज...

कैग की रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला पहलू पंचायतों में व्याप्त प्रशासनिक शून्यता है। रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार,प्रदेश की पंचायतों में स्वीकृत कुल पदों में से 61 प्रतिशत पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। इन रिक्तियों के कारण पंचायत कार्यालयों में रोजमर्रा का काम ठप होने की स्थिति में है। जब पदों पर उपयुक्त कर्मचारी ही नहीं होंगे, तो सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक कैसे पहुंचेगा? यह स्थिति न केवल योजनाओं की गति को धीमा कर रही है, बल्कि जवाबदेही तय करने में भी बड़ी बाधा उत्पन्न कर रही है। रिपोर्ट ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इन पदों को जल्द भरा जाए ताकि कामकाज पटरी पर आ सके।

वित्तीय अनियमितताएं और फंड की भारी कमी...

वित्तीय प्रबंधन के मोर्चे पर भी छत्तीसगढ़ की स्थिति चिंताजनक बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार,स्थानीय निकायों को राज्य और केंद्र से मिलने वाली तय राशि के मुकाबले करीब 3,243 करोड़ रुपये कम फंड जारी किए गए। फंड की इस भारी कटौती ने कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को अधर में लटका दिया है। विकास कार्यों के लिए राशि उपलब्ध न होना ग्रामीण विकास की नींव को कमजोर करने वाला है। कैग ने सिफारिश की है कि स्थानीय निकायों को समयबद्ध तरीके से फंड उपलब्ध कराया जाए ताकि ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास न रुके। सरकार ने पंचायतों में डिजिटल पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से 'ई-ग्राम स्वराज' पोर्टल लागू किया था,लेकिन रिपोर्ट में यह उजागर हुआ है कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है।

शराब घोटाला...104 करोड़ कांग्रेस भवन पहुंचे,रामगोपाल अरेस्ट

ईओडब्ल्यू का दावा...जब्त डायरी की दोबारा जांच में मिले सबूत,22 जुलाई तक रिमांड पर...

रायपुर,18 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने शनिवार को उन्हें रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया। कोर्ट ने कोल लेवी घोटाले में 22 जुलाई तक पुलिस रिमांड बढ़ा दी है। इसी बीच ईओडब्ल्यू ने उन्हें लिकर स्कैम घोटाले में भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, ओवरटाइम घोटाले में पूछताछ करने की अनुमति भी कोर्ट से मिल गई है। ईओडब्ल्यू का दावा है कि 104 करोड़ रुपए कांग्रेस भवन पहुंचाए गए।

ईओडब्ल्यू का नया दावा-104 करोड़ रुपए कांग्रेस भवन पहुंचे : रिमांड के दौरान ईओडब्ल्यू ने कोर्ट को बताया कि,जांच में अब तक मिले तथ्यों के आधार पर करीब 104 करोड़ रुपए कांग्रेस भवन तक पहुंचने की जानकारी मिली है। एजेंसी का कहना है कि डायरी और अन्य दस्तावेजों की दोबारा जांच में यह जानकारी सामने आई है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और ईओडब्ल्यू दोनों ने दावा किया था कि कोल लेवी से जुड़े 52.62 करोड़ रुपए रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचे थे। बाद में यह आंकड़ा 54.62 करोड़ रुपए बताया गया था। अब ईओडब्ल्यू ने जांच के दौरान यह दावा बढ़ाकर 104 करोड़ रुपए कर दिया है।

डायरियों के आधार पर जांच आगे बढ़ी : जांच एजेंसी के मुताबिक, कोल लेवी मामले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी और अन्य लोगों के ठिकानों से मिली डायरियों के विश्लेषण के आधार पर यह जांच आगे बढ़ी है। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर कथित रकम के लेन-देन की पड़ताल की जा रही है।

इन आरोपियों से आमना-सामना कराएगी ईओडब्ल्यू : ईओडब्ल्यू ने कोर्ट को बताया कि रामगोपाल अग्रवाल का आमना-सामना इस मामले के अन्य आरोपियों और गवाहों से कराया जाएगा। इनमें सूर्यकांत तिवारी, देवेंद्र डनसेना,निखिल चंद्राकर,रोशन सिंह, नारायण साहू और गवाह मोहसिन खान शामिल हैं। एजेंसी का कहना है कि इस दौरान मामले से जुड़े दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जब्त किए जाएंगे।

रिमांड के दौरान ही शराब घोटाले में दूसरी गिरफ्तारी : कोल लेवी मामले में 9 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद ईओडब्ल्यू ने रामगोपाल अग्रवाल को स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने कोल लेवी मामले में 22 जुलाई तक पुलिस रिमांड बढ़ा दी। इसी दौरान ईओडब्ल्यू ने उन्हें शराब घोटाले में भी गिरफ्तार के आवेदन लगाया था हालांकि, इस मामले में कोर्ट ने 25 जुलाई तक रामगोपाल को न्यायिक हिरासत का आदेश दिया। चूंकि कोल लेवी मामले में वे पहले से ईओडब्ल्यू की पुलिस रिमांड पर हैं, इसलिए फिलहाल वे एजेंसी की हिरासत में ही रहेंगे। 22 जुलाई को कोल लेवी मामले की रिमांड खत्म होने के बाद ईओडब्ल्यू शराब घोटाले में अलग से पुलिस रिमांड मांग सकती है।

टिकरापारा 5 की संदिग्ध मौत मामले में सूदखोर मुन्ना ठाकुर से पूछताछ जारी

रायपुर,18 जुलाई 2026। राजधानी रायपुर के टिकरापारा संजय नगर इलाके से एक बड़ी और बेहद ही रुला देने वाली घटना सामने आई है जिसमें परिवार की मुखिया द्वारा जब अपने बच्चों को देर रात खाना खिलाया गया उन बच्चों को यह नहीं पता था कि वह उनकी जिंदगी का आखिरी खाना होगा। संजय नगर के एक घर में पांच लाशें मिलने से ही पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई है और आसपास के लोगों का यह कहना है कि घर का जो मुखिया है साजिद वह कर्ज में डूबा हुआ था उसी के चलते सूदखोर मुन्ना ठाकुर नाम के व्यक्ति को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है और उससे भी मामले की पूछताछ जारी है। साजिद मौदहापारा इलाके में बैटरी रिपेयरिंग का काम करता था और लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। बैंक की ईएमआई के साथ निजी उधारी का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा था। परिजनों और स्थानीय लोगों के मुताबिक, कर्ज की वसूली के लिए लोग अक्सर उसके घर पहुंचते थे, जिससे परिवार में तनाव और विवाद की स्थिति बनी रहती थी। पुलिस इस आर्थिक दबाव को घटना की एक प्रमुख वजह मानकर जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक,संजय नगर निवासी सय्यद उमेर अली के मकान में सय्यद शाहिद उर्फ सज्जू (45) पिछले आठ महीने से किराए पर रह रहा था। उसके साथ पत्नी राबिया, बेटा इरशाद अली (19), बेटी शाहिदा (17) और इरशाबा बेगम (16) भी रहती थीं। शाहिद पुरानी बैटरियों की खरीद-बिक्री का कारोबार करता था।

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली डंप से हथियार और विस्फोटक बरामद

नारायणपुर,18 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षाबलों ने जंगल में छिपाकर रखा गया नक्सलियों का डंप बरामद किया है। इसमें हथियार,विस्फोटक,संचार उपकरण, इलेक्ट्रानिक सामग्री, चिकित्सा सामग्री,नक्सल साहित्य और अन्य सामग्री है। बरामद 44 बीजीएल शेल को सुरक्षा की दृष्टि से बम निरोधक दस्ते (बीडीएस) ने मौके पर ही सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया। नारायणपुर एसपी संदीप कुमार पटेल के अनुसार बीएसएफ की 133वीं वाहिनी, सोनपुर की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कदेर के जंगल में नक्सलियों ने बड़ी मात्रा में सामग्री छिपाकर रखा है। इस सूचना के आधार पर टीम ने क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान बम निरोधक दस्ते ने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए संदिग्ध स्थान की जांच की। खुदाई के दौरान जमीन के भीतर से हथियार और अन्य नक्सल सामग्री बरामद हुई। बरामद सामग्री में एक 303 राइफल, छह 315 राइफल,एक 12 बोर बंदूक,दो बीजीएल,विभिन्न प्रकार के 179 कारतूस,.303 राइफल की मैगजीन,आरएफ डिटेक्टर, एंटीना, आइडी आपरेटिंग मैकेनिज्म,जीपीएस,नक्सली वर्दी,नक्सली बैनर,फोटो,बड़ी मात्रा में नक्सली साहित्य,चिकित्सा सामग्री,जनरेटर मैनुअल,छह पेन ड्राइव, 78 मेमोरी कार्ड तथा अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री शामिल है। सुरक्षा कारणों से बरामद 24 बड़े और 20 छोटे, कुल 44 बीजीएल शेल को बीडीएस ने मौके पर ही निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया।

छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओवरटाइम घोटाला...अरुणपति त्रिपाठी अरेस्ट

रायपुर,18 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 172 करोड़ के कथित ओवरटाइम भुगतान घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। ईओडब्ल्यू-एसीबी ने तत्कालीन प्रबंध संचालक (एमडी) अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। उन पर फर्जी भुगतान मामले में कमीशन लेने का आरोप है। अरुणपति त्रिपाठी को 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। शनिवार को रायपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 20 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जांच एजेंसी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने 29 नवंबर 2023 को 3 लोगों से 28.80 लाख कैश जब्त किए थे। इस संबंध में राज्य शासन को सूचना भेजी गई थी, जिसके आधार पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि साल 2019-20 से 2023-24 के बीच कर्मचारियों के ओवरटाइम, चार अतिरिक्त दिवस, बोनस और सर्विस चार्ज के नाम पर मैनपावर एजेंसियों को 172 करोड़ से अधिक का अवैध भुगतान किया गया।

108 दिनों में लाखों जिंदगियों की उम्मीद बनी '108 संजीवनी एक्सप्रेस'

नई एम्बुलेंस सेवा ने आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को दी नई रफ्तार,हजारों मरीजों को समय पर मिला जीवनरक्षक उपचार

-संवाददाता-

रायपुर,18 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, त्वरित और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई नई '108 संजीवनी एक्सप्रेस' ने अपने संचालन के मात्र 108 दिनों में उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की हैं,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुई यह सेवा आज प्रदेश के दूरस्थ वनांचलों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक लाखों लोगों के लिए जीवनरक्षक व्यवस्था बन चुकी है, आधुनिक एम्बुलेंस, प्रशिक्षित इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन,जीपीएस आधारित मॉनिटरिंग और 24म7 केंद्रीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के कारण यह सेवा प्रदेशवासियों के बीच भरोसे का प्रतीक बन गई है।

108 दिनों में सेवा ने बनाए कई रिकॉर्ड

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 108 दिनों में करीब 2.96 लाख आपातकालीन कॉल प्राप्त हुई, इनमें से 86,500 से अधिक मरीजों तक समय पर एम्बुलेंस पहुंची, विभाग का दावा है कि सेवा ने अधिकांश मामलों में निर्धारित समय के भीतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हुए हजारों मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाया।

सड़क दुर्घटनाओं से लेकर प्रसव तक बनी जीवनरक्षक सेवा

नई 108 संजीवनी एक्सप्रेस केवल दुर्घटना पीड़ितों तक सीमित नहीं रही, पिछले 108 दिनों में 6,500 से अधिक सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सहायता दी गई,वहीं 5,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इसके अलावा 174 नवजात एवं शिशुओं को विशेष चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई तथा 5,300 से अधिक हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मरीजों को गोल्डन ऑवर के भीतर उपचार केंद्र तक पहुंचाया गया।

अस्पताल पहुंचने से पहले ही शुरू हो जाता है इलाज

नई व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एम्बुलेंस केवल मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने का माध्यम नहीं है,बल्कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीज का प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया जाता है,आधुनिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस एम्बुलेंसों में मौजूद प्रशिक्षित EMT मरीज की स्थिति के अनुसार आवश्यक चिकित्सा सहायता देते हैं,जिससे गंभीर मरीजों के बचने की संभावना बढ़ जाती है।

375 अत्याधुनिक एम्बुलेंसों का मजबूत नेटवर्क

प्रदेशभर में वर्तमान में लगभग 375 आधुनिक एम्बुलेंसों का संचालन किया जा रहा है, इनमें 300 बेसिक लाइफ सपोर्ट , 70 एडवांस लाइफ सपोर्ट और 5 विशेष ALS Neonatal एम्बुलेंस शामिल हैं,यह नेटवर्क दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों,ग्रामीण इलाकों,राष्ट्रीय राजमार्गों और शहरों तक समान रूप से स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहा है। विभाग के अनुसार लगभग 3.11 करोड़ आबादी इस सेवा के दायरे में है।

प्रतिक्रिया समय में आया बड़ा सुधार-स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि नई प्रणाली लागू होने के बाद एम्बुलेंस के प्रतिक्रिया समय में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में औसतन 12 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 18 मिनट के भीतर एम्बुलेंस मरीज तक पहुंच रही है, चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि दुर्घटना, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर परिस्थितियों में यह समय मरीज की जान बचाने में निर्णायक भूमिका निभाता है।

कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हो रही हर एम्बुलेंस की निगरानी

सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए राज्य स्तर पर स्थापित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से प्रत्येक एम्बुलेंस की रियल-टाइम निगरानी की जा रही है। कॉल रिस्पांस, वाहन उपलब्धता,डिस्पैच समय,प्रतिक्रिया समय और सेवा गुणवत्ता जैसे सभी प्रमुख संकेतकों की नियमित समीक्षा की जाती है,जिससे नागरिकों को तेज,सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

स्वास्थ्य विभाग ने टीम को दी बधाई...

नई 108 संजीवनी एक्सप्रेस के सफलतापूर्वक 108 दिन पूरे होने पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने सेवा से जुड़े इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन,पायलट,इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर,जिला समन्वयकों और अन्य कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि विभाग की दूरदर्शी योजना,प्रभावी प्रबंधन और कर्मचारियों की निष्ठा का परिणाम है। अधिकारियों ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भी यह सेवा प्रदेशवासियों को समयबद्ध,निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती रहेगी।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)